

साप्ताहिक

# शांति मिशन

नई दिल्ली

वर्ष-28 अंक- 48

28 नवंबर - 04 दिसंबर 2021

पृष्ठ 12

अन्दर पढ़िए

आज फिर नेहरु और पटेल  
की ज़रूरत

पृष्ठ - 6

भारत में भ्रष्टाचार का फैलता नासूर

पृष्ठ - 7

## उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पंजाब, मणिपुर और गोवा के विधानसभा चुनाव-2022

### विपक्षी गठबंधन, समय की अहम ज़रूरत

**जब सत्ता पर कोई एक दल अपना दबदबा बना लेता है तो उसे केवल विपक्षी गठबंधन ही चुनौती दे सकता है, हमारा राजनीतिक इतिहास यही बताता है।**

अगले वर्ष 2022 में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। सभी की निगाहें इस पर हैं कि भाजपा का इन राज्यों में कैसा प्रदर्शन रहेगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में अगले वर्ष की शुरूआत में चुनाव हैं। इसमें भाजपा पंजाब को छोड़कर जहां कांग्रेस की सरकार है बाकी चार राज्यों में अपनी सरकार को बचाने के लिए लड़ा है। चूंकि कोरोना की दूसरी लहर के बाद पहले विधानसभा चुनाव हैं, इसलिए लोगों में जिजासा है कि कुछ राज्यों में दूसरी लहर के कुप्रबंधन के आरोपों का भाजपा को कितना नुकसान होगा।

किसानों के आंदोलन से उपजी पृष्ठभूमि (हालांकि प्रधानमंत्री ने कृषि कानून वापसी की घोषणा कर दी है) और लखीमपुर खीरी में मोदी कैबिनेट के गृह मंत्रालय के मंत्री के बेटे तथा स्थानीय सांसद पर चार किसानों को गाड़ी से कुचलने के आरोपों ने भाजपा की मुश्किलें बढ़ाई हैं। कई लोग मान रहे हैं कि भाजपा को यूपी समेत कुछ राज्यों में काफी हद तक इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। लेकिन अगर यह मानता है कि ये घटनाक्रम इन चुनावों में भाजपा को हराने के लिए पर्याप्त होंगे, तो यह उसकी ग़लतफहमी है। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, वहां शायद भाजपा 2017 विधानसभा चुनावों जितनी लोकप्रिय न हो, लेकिन चुनावी मुकाबले की प्रकृति का भाजपा को ज़रूर लाभ मिलेगा। कई राज्यों में बहु कोणीय मुकाबले की संभावना है, जिससे भाजपा विरोधी वोट बंट जाएंगे और फायदा भाजपा को ही होगा। भाजपा विरोधी वोटों के बंटने से कांग्रेस भले ही भाजपा को हराने में सक्षम न हो, लेकिन

2022 के विधानसभा चुनावों के बाद कई राज्यों में मुख्य विपक्ष बनकर उभर सकती है। आम आदमी पार्टी (आप) और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) आगामी चुनावों के लिए गंभीर प्रयास कर रही हैं, जिससे कांग्रेस की संभावनाओं को नुकसान होगा क्योंकि ये पार्टियां कुछ वोट अपने हिस्से लाएंगे, जो भाजपा के लिए पर्याप्त होंगे, भले ही उसका वोट शेयर भी थोड़ा बहुत बढ़ जाए, लेकिन फिर भी अगर वह अकेले चुनाव लड़ती है तो भाजपा को चुनौती देती नहीं दिखती।

प्रियंका गांधी वाड़ा ने लखीमपुर खरी घटना के खिलाफ़ प्रदर्शन किया था और उसके कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में 40 प्रतिशत महिलाओं को टिकट देने घोषणा उसको लाभ देगी ये तो आने वाला समय ही बतायेगा। जिन्हें लगता है कि ये बातें कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में गेमचेंजर साबित होंगी, ये ग़लत हैं। कांग्रेस को पिछले 3 चुनावों में करीब 6 प्रतिशत वोट मिले थे, इसलिए सिर्फ़ प्रदर्शन और प्रतीकवाद के सहारे वह वापसी नहीं कर पाएगी। कांग्रेस का 40 प्रतिशत महिलाओं को उम्मीदवारी देने का फैसला बड़ा क़दम है, लेकिन यह बहुत देर से उठाया गया है और महिला वोटों को समर्थन हासिल

करने के लिए पर्याप्त होगा या नहीं यह अभी भविष्य के गर्भ में है। कांग्रेस यूपी के इन चुनावों में एजेंडा तयकर पाई है और शायद उसका वोट शेयर भी थोड़ा बहुत बढ़ जाए, लेकिन फिर भी अगर वह अकेले चुनाव लड़ती है तो भाजपा को चुनौती देती नहीं दिखती।

अगर समाजवादी पार्टी और बसपा एक दूसरे के खिलाफ़ खड़े रहेंगे, तो वे भाजपा को चुनौती नहीं दे पाएंगे। दोनों पार्टियों के पास करीब 20-20 प्रतिशत वोट है। सपा के मुख्य समर्थक यादव हैं, जबकि दलितों, ख़ासतौर पर जाटव समुदाय में बसपा का जनाधार है। दोनों ही पार्टियों को तो गठबंधन बनाने की ज़रूरत है, तभी भाजपा विरोधी वोटों का बंटना कम होगा। आदर्श रूप से इस गठबंधन में कांग्रेस और राष्ट्रीय लोक दल को भी शामिल होना चाहिए जिससे अतिरिक्त वोट जुटाए जा सकें।

2017 के विधानसभा चुनावों के दौरान 39 प्रतिशत वोट हासिल करने वाली भाजपा को हराने के लिए, किसी भी पार्टी को उससे लगभग 7-8 फीसदी वोट हासिल करने की ज़रूरत है और इन वोटों को सबसे बड़े विपक्षी दल द्वारा ही हासिल किया जाना चाहिए। इसका कोई कारण नहीं है कि भाजपा 8 फीसदी

वोट न खाए, लेकिन इसकी थोड़ी बहुत संभावना है कि सपा को 8-9 फीसदी वोटों का लाभ हो जाए जो कि 2017 में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी थी। अगर उत्तर प्रदेश में विपक्ष एक हो जाता है तो भाजपा के लिए होने वाला यह नुकसान एक जुट विपक्ष के लिए लाभकारी हो सकता है (बशर्ते वे गठबंधन बनाएं)।

कहा जा रहा है कि उत्तराखण्ड में लोग भाजपा के पांच वर्ष के शासन से बहुत खुश नहीं हैं। भले ही लोगों ने भाजपा को राज्य में प्रचंड बहुमत दिया था, लेकिन भाजपा वहां अस्थिर बनी रही और पार्टी ने तीन मुख्यमंत्री बदले। 2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबला था और कांग्रेस के पास भाजपा को हराने का अवसर था। लेकिन अब चुनावी मुकाबले में 'आप' के आ जाने से उसके लिए यह आसान नहीं होगा। राज्य के मतदाताओं ने पहले चुनावों में तीसरे विकल्प की तलाश की ओर झुकाव दिखाया है। दो परंपरिक प्रतिद्वंदी भाजपा और कांग्रेस को मिलाकर केवल 60-65 प्रतिशत वोट ही मिले हैं। अब उत्तराखण्ड के मतदाताओं के पास 'आप' का विकल्प भी है। 'आप' भले ही अपने बूते चुनाव न जीत पाए, लेकिन उसे इतने वोट तो मिल ही सकते हैं जो

कांग्रेस की संभावनाओं और भाजपा की आशाओं को नुकसान पहुंचा सकता है इससे दो पार्टियों को फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी।

गोवा के चुनावी मैदान में टीएमसी और 'आप' के आने से राज्य में बहुकोणीय मुकाबला हो सकता है। विभाजित विपक्ष के कारण भाजपा विरोधी वोट बंटेंगे, जिससे भाजपा को लाभ होगा। उधर गोवा में कांग्रेस अब 2017 की कांग्रेस जैसी नहीं रही क्योंकि कई नेता दल बदल चुके हैं और अन्य पार्टियों में शामिल हो गए हैं, मुख्य रूप से भाजपा में। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री लुइज़िन्हो फलेरियो कांग्रेस से टीएमसी में चले गए। जहां तक प्रश्न मणिपुर का है, तो बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा कि भाजपा चुनाव से पहले या चुनाव के बाद भी गठबंधन कैसे बनाती है।

इतिहास बताता है कि भारत में जब किसी एक राजनीतिक पार्टी का दबदबा हो जाए तो विपक्ष ही उसे चुनौती दे पाता है। वर्ष 1977 और 1989 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को तब झटका लगा जब जनता पार्टी/जनता दल के धड़े इसके खिलाफ़ एक जुट हो गए। 1998 और 1999 के लोकसभा चुनाव के दौरान, कांग्रेस को भाजपा ने चुनौती दी, जब उसने विभिन्न क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया। एनडीए सरकार को 2004 और 2009 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने चुनौती दी थी, जब उसने क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया था। भाजपा को एक जुट विपक्ष ही चुनौती दे सकता है भारत के लोगों के वर्तमान राजनीतिक मिजाज़ को देखते हुए कोई और भाजपा को चुनावी दौड़ में पीछे नहीं धकेल सकता।

**हम बाइचांस नहीं बाई चॉइस इंडियन हैं : मौलाना महमूद मदनी**

जमीयत उलेमा-ए-हिन्द के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जिन्होंने को बयान से किनारा करते हुए कहा कि मुसलमानों ने जिन्होंने को आइडिया को रिजेक्ट किया और भारत को चुना है। हम लोग बाइचांस नहीं बाई चॉइस इंडियन हैं। हमने भारत को चुना है। मौलाना मदनी ने कहा कि जिन्होंने इंडिया के मुसलमानों का जनाज़ा पढ़कर गए थे। एक टीवी चैनल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मौलाना महमूद मदनी ने देश में मुसलमानों की स्थिति, सरकार के रवैये और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जिन्होंने बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी।

# चीन में मुसलमानों की दुर्दशा का लघु इतिहास

चीन अपने मुसलमानों के साथ कैसा बर्ताव करता है, इसे कोई ठीक से जाने तो उसके रोगटे खड़े हो सकते हैं। वैसे तो रूस, जापान और कोरिया जैसे कई देशों में भी मुसलमानों की बड़ी दुर्दशा होती रही है लेकिन चीन उनके लिए एक तरह से भयानक यंत्रणा-घर बन चुका है। आश्चर्य की बात यह है कि पाकिस्तान जैसा देश, जो इस्लाम के नाम पर बना दुनिया का अकेला देश है, वह भी चीन के मुसलमानों पर हो रहे जुल्मों के खिलाफ़ मौन साथे रहता है। ताज़ा खबर यह है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन कई शहरों में बनी मस्जिदों की मीनारें और गुंबदों को ढहाने का आदेश जारी कर दिए हैं। उनका कहना है कि ये मीनारें और गुंबद वगैरह चीनी वास्तुकला के विपरीत हैं। इस अरबी वास्तुकला की अंधी नक़्ल चीनी संस्कृति के विरुद्ध है। जिन्हें चीन में रहना है, उन्हें किसी विदेशी संस्कृति की नक़्ल से मुक्त रहना होगा।

ऐसा नहीं है कि चीनी मुसलमानों का यह चीनीकरण राष्ट्रपति शी

जिनपिंग ने ही शुरू किया है। यह वहाँ सदियों से होता चला आया है। यदि आप लगभग 1300 वर्ष पहले सियान में बनी मस्जिद का चित्र देखेंगे, तो उपरको ऐसा लगेगा, जैसा कि वह

कोई बौद्ध मंदिर है। मैंने अपनी कई चीनी यात्राओं के दौरान उरुमनी, केंटन, शंघाई और बीजिंग जैसे शहरों में मस्जिदों को चीनी वास्तु कला के ढांचे में ढला हुआ पाया है। यह माना

जाता है कि सन 616-18 के आसपास तांग राजवंश के काल में कुछ अरब और ईरानी व्यापारियों ने चीन तक पहुंचने की हिम्मत की और उन्हें चीनी सप्नाट ने यह छूट दी कि वे

## अबू धाबी:- गैर मुस्लिमों को शादी तलाक की आज़ादी

शरिआ क़ानून से शासित संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की राजधानी में रह रहे गैर मुस्लिमों के लिए एक अच्छी ख़बर है। अबू धाबी में गैर मुस्लिमों को अब नए नागरिक क़ानून के मुताबिक शादी करने, तलाक़ देने और बच्चे की साझा कस्टडी हासिल करने का अधिकार मिल जाएगा। यूएई के शासकों की ओर से जारी नए आदेश में इसकी अनुमति दी गई है। यह नियम सिर्फ अबू धाबी में ही लागू होंगे।

यूएई की राजधानी अबू धाबी में गैर मुस्लिमों के लिए तलाक़, विरासत और बच्चों की निगरानी व देखभाल संबंधित नए नियम जारी किए गए हैं। समाचार एजेंसी डब्ल्यूएम ने जानकारी दी कि अबू धाबी ऐसे मामलों के लिए नई अदालत गठित करेगा जिनमें अरबी और अंग्रेज़ी, दोनों भाषाओं में कामकाज हो सकेगा। यह अमीरात में बड़ी संख्या में व्यावसायिक हब बन रहे अन्य क्षेत्रों पर प्रतिबद्धता से बढ़त हासिल करने के लिए यह नया आदेश जारी किया है। जानकारी के मुताबिक, नियमों में बदलाव के बाद माता-पिता अपने बच्चों की निगरानी और देखभाल को साझा कर सकेंगे। इसके अलावा कानून में शदियों का विचार भी पेश किया है और वसीयत करने की भी इजाज़त होगी। अभी तक अबू धाबी में शादी और तलाक़ पर क़ानून अन्य खाड़ी देशों की तरह से इस्लामिक शरीया कानून पर आधारित थे। अबू धाबी के शेष ख़लीफ़ा बिन ज़ायद अल नहयान की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यह सिविल मैरिज़, तलाक़, गुज़ारा भत्ता, बच्चों की संयुक्त कस्टडी, पितृत्व का सबूत और उत्तराधिकारी सभी को समाहित करता है।

यह दिल्ली है .....

यह दिल्ली है .....

यह दिल्ली है .....

## राष्ट्रीय राजधानी को प्रदूषण मुक्त करना बड़ी चुनौती

उच्चतम न्यायालय द्वारा केन्द्र और दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार के बावजूद दिल्ली में प्रदूषण का स्तर भयावह बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने तो लॉकडाउन जैसे उपायों का सुझाव भी सरकारों को दिया है। यह साबित हो चुका है कि आधी कारों को हर रोज़ पर रोकने से दिल्ली में वायु प्रदूषण में ज़्यादा कमी नहीं आने वाली हैं फिर सार्वजनिक प्रणाली की हालत ऐसी नहीं है कि दिल्ली सरकार निजी कारों के सम-विषम का फिर प्रयोग कर सके। दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और सरकार के अधीन चलने वाली बसों के अलावा अभी स्कूल बसों को सड़कों पर आने नहीं दिया गया है। दिल्ली की जीवन रेखा मेट्रोल रेल को तमाम एहतियात के तहत चलाया जा रहा है। कोरोना से बचाव के लिए अधिक संख्या में लोग अपने वाहनों का उपयोग कर रहे हैं। ज़ाहिर है इससे सड़कों पर भी दिखने लगी है और सामान्य दिनों से उलट उन इलाकों में भी दिन में ही जाम लगने लगा है जहाँ पहले

यह नहीं लगता था। इस जाम के कारण प्रदूषण ज़्यादा हो जाता है और बीच सड़क पर सांस लेना कठिन होने लगता है।

दिल्ली सरकार ने 2016 में दो बार और 2019 में एक बार 25 लाख कारों को सम-विषम के आधार पर चलाया यानि एक दिन सम नंबर की कारों और दूसरे दिन विषम नंबर की कारों चलाई गई। इस का कुछ लाभ हुआ लेकिन बेहतर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था न होने से उस दौरान लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। इस बार दिल्ली में लाल बत्ती पर गाड़ियों के इंजन बंद करवाने का अभियान चलाया जा रहा है।

पहले अवैध औद्योगिक इलाक़े, एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले ट्रक बस आदि के चलते भी दिल्ली और एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना) में प्रदूषण बढ़ाने का कारण माने जाते थे। वैसे अभी भी अवैध, उद्योग हैं, भले ही उनकी संख्या कम हुई हो। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए किसी भी दिन नहीं दिया है।

उत्पादन इकाई को लाइसेंस देने पर पांचांदी लगा दी है। दिल्ली के चारों ओर ईस्टर्न पेरिफेरियल और वेस्टर्न पेरिफेरियल सड़क बन जाने से दिल्ली होकर एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले ट्रकों का दिल्ली के भीतर आना कम हुआ है। देश के सड़क परिवहन ने कुछ वर्ष पहले दावा किया था कि उनका मंत्रालय दिल्ली के लिए 50 हज़ार करोड़ की परियोजना पर काम कर रहा है दो वर्ष में दिल्ली में वायु प्रदूषण काफ़ी कम हो जाएगा। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) समेत अनेक अदालतों ने दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए बार-बार कहा है।

दिल्ली/एनसीआर में प्रदूषण की एक बड़ी वजह पराली जलाना भी माना जाता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसान खेत ख़ाली करके दूसरी फसल लगाने के लिए खेत में बच्ची फसलों के अवशेष को जलाते हैं, जिसका धुआं दिल्ली पर छा जाता है।

अदालती आदेश के बाद सरकारों ने पराली न जलाने और उसका दूसरा कम करने के लिए किसी भी नई

बेहतर उपयोग करवाने के प्रयास शुरू किए हैं। इसी तरह से एनजीटी ने दस वर्ष पुराने व्यवसायिक वाहनों पर रोक परिफेरियल सड़क बन जाने से दिल्ली होकर एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले ट्रकों का दिल्ली के भीतर आना कम हुआ है। बावजूद इसके इस बार प्रदूषण कम होता नहीं दिख रहा है। दिल्ली में पहले भी सारे व्यावसायिक वाहनों को अदालती आदेश से सीएनजी पर चलाया जा रहा है। हालात एक दिन में ख़राब नहीं हुए हैं। कुप्रबंधन और सरकारी लापरवाही ने दिल्ली के हालात बदतर बना दिए और सुधार के आसार दिख नहीं दिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई 1998 को आदेश दिया कि दिल्ली में चलने वाले सभी बसों को धीरे धीरे सीएनजी पर लाया जाए।

इसकी तारीख 31 मार्च 2001 तय की गई। सरकारें एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालती रहीं तो अप्रैल 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा सख्त आदेश दिए। उसके बाद सीएनजी पर बसों और व्यावसायिक वाहनों को लाने की प्रक्रिया तेज़ हुई। कायदे में 2010

### वेद प्रताप वैदिक

अपना धर्म प्रचार भी करें। धीरे-धीरे कजाक, उज़बेक, ताजिक, तुर्कमान और किरगिज लोग, जो मध्य एशिया में रहते थे, वे भी आकर चीन में बसने लगे हैं। इस समय चीन में मुसलमानों की संख्या दो करोड़ से भी ज्यादा है।

हज़ार-बारह सौ साल पहले जब ये मुसलमान चीन में आए तो उन्होंने चीनी औरतों से शादियां कीं। वे पूरी तरह से चीनी ही बन गए। वे वहाँ रहते हुए चीनी भाषा बोलने लगे, चीनी वेश भूषा पहनने लगे और यहाँ तक कि उनके रीत रिवाज़ भी चीनियों से काफ़ी हद तक मिलने जुलने लगे। उन्हें 'हुई मुसलमानों' के नाम जाना जाने लगा लेकिन परवर्ती चीनी शासकों, विशेषकर मंगोल शासक चंगज़ ख़ान और कुबलई ख़ान के ज़माने में चीनी मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा सख्ती बरती गई। उन्हें हलाल का मास खाने से रोका गया। उनके अरबी फारसी नामों पर ऐतराज़ किया गया। मुसलमानों बाकी पेज 11 पर

## और किसान जीत गए!

आखिरकार सरकार को झुकना ही पड़ा। वर्षभर से आंदोलन कर रहे किसान जीते और प्रधानमंत्री विवादस्पद कृषि कानूनों को वापस लेने का एलान करने पर मजबूर हो गए। इस घोषणा के समय नरेन्द्र मोदी जी ने कहा कि 'शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रह गई होगी' अब उन्हें कौन बताए कि तपस्या इन्होंने की है या किसानों ने जिन्होंने सर्दी, गर्मी, बरसात और लोहे की किलें गाड़ें जाने के बावजूद यह आंदोलन जारी रखा असली तपस्या किसने की इसका स्पष्टीकरण हर कोई दे सकता है। फिलहाल तीन कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला सरकार को आने वाले समय में क्या फल देगा और इसके क्या परिणाम निकलेंगे यह तो अभी भविष्य के गर्भ में है। हालांकि किसान अभी भी एमएसपी की मांग पर अड़े हैं और सरकार से एमएसपी गारंटी कानून की मांग रहे हैं। लखनऊ में महाकिसान पंचायत में भी संयुक्त किसान मोर्चा ने यही मांग दोहराई। यह आंदोलन ऐतिहासिक बन चुका है, महात्मा गांधी के देश में साल भर से चल रहे इस शांतिपूर्ण आंदोलन पर दुनियाभर की नज़रें टिकी थीं। सरकार की किरकिरी हो रही थी। भले ही किसानों ने अपने आंदोलन का स्वरूप गैर राजनीतिक रखा हो, लेकिन यह हक़ीक़त है कि इसे विपक्षी दलों समाज के तमाम वर्गों, कारोबारियों, ब्यूरोक्रेसी और भारतीय जनता पार्टी की अनेक उपधाराओं का समर्थन हासिल था।

राष्ट्रपति के संवैधानिक प्रतिनिधि एक राज्यपाल सतपाल मलिक तो खुल्लम-खुल्ला किसान आंदोलन को समर्थन दे चुके थे। इसे राष्ट्रपति भवन का मूक-समर्थन भी मान लिया गया था। यदि राष्ट्र अपने राज्यपाल से सहमत नहीं होते तो अब वह उन्हें हटा चुके होते या उनसे इस्तीफा ले चुके होते। चूंकि राष्ट्रपति बजट सत्र की शुरुआत अपनी सरकार की उपलब्धियों से ही करते हैं और संविधान भी केन्द्र सरकार को राष्ट्रपति की सरकार मानता है, ऐसे में बहस यह भी छिड़ गई थी कि क्या राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। प्रश्न यह है कि सत्याग्राही किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, देशद्रोही, विदेशी पैसे पर चलने वाला बताने के बाद केन्द्र सरकार को यू-टर्न क्यों लेना पड़ा। आजादी के बाद पहली बार किसी गैर कांग्रेस पार्टी ने अपने दम पर बहुमत हासिल किया था और इसी दम के साथ राज कर रही पहली गैर कांग्रेसी पार्टी ने घुटने क्यों टेके? इन प्रश्नों का उत्तर किसी ताले में बंद नहीं है।

यह छुपा हुआ नहीं है कि महाराष्ट्र और बंगाल के विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा अपने बेहद कठिन दौर से गुज़र रही है। दक्षिण में इसका वजूद असरदार नहीं है। पूरब और पश्चिम में वह पटखनी खा चुकी है। अब इसके कामकाज का लिटमस टेस्ट उत्तर में होने वाला है। उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड में विधानसभा चुनाव सिर पर हैं। योगी सरकार का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा है। लखीमपुर खीरी हादसे ने लोगों को हिला दिया है, उसमें एक केन्द्रीय मंत्री और उनके बेटे की भूमिका ने उन्हें खलनायक बना दिया है। इसके अलावा पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल घड़ी है। वहां दशकों पुराना उसका सहयोगी अकाली दल छिटक गया है। अब कांग्रेस से किनारा कर चुके पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा के लिए कुछ सहारा बन सकते हैं, लेकिन वे तभी समर्थन देने या लेने को तैयार थे, जबकि केन्द्र सरकार कृषि कानूनी वापस लेती। इसी कड़ी में उत्तराखण्ड में मुख्यमंत्री बदलने के बाद भी अंतर्कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। ऊपर से केन्द्र सरकार की नाकामियों के प्रेरण भी मंडरा रहे हैं।

किसान आंदोलन चुनाव वाले प्रदेशों में एक गंभीर मुद्दा बनकर उभरा है। इस आंदोलन के चलते भारतीय जनता पार्टी के पास मतदाता के सामने जाने का कोई नैतिक आत्मबल नहीं बचा था। अन्य प्रदेशों में तो एक बार पार्टी सारा ज़ोर लगाकर चुनाव मैदान में कूद सकती थी लेकिन उत्तर प्रदेश का मामला अलग है। इस राज्य से राष्ट्रपति चुने गए हैं, प्रधानमंत्री चुने गए हैं, रक्षामंत्री निर्वाचित हैं, और भी कई केन्द्रीय मंत्री इस प्रदेश से हैं, पार्टी का सबसे बड़ा हिन्दू चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में उनके साथ है, राहुल गांधी को कांग्रेस के गढ़ में हराने वाली स्मृति ईरानी जैसी फायर ब्रांड नेत्री इसी राज्य से हैं और आधा गांधी खानदान भाजपा के साथ है (यह बात अलग है कि वरुण गांधी और मेनका गांधी इन दिनों अपने दल से प्रसन्न नहीं हैं) इसके अलावा प्रदेश की बड़ी समस्याओं से निपटने में सरकार विफल रही है।

हाल ही में कांग्रेस पार्टी की नेत्री प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की रैलियों में जिस तरह लोग उमड़े हैं, उसने यकीनन भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा दी होगी। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपनी हार पचा नहीं पाएगी। यह उसके अपने राजनीतिक भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। तीनों कृषि कानून जिस ढंग से संसद में पास कराए गए थे, इसे पूरे देश ने देखा था। इससे केन्द्र सरकार की बदनामी ही हुई थी। जानकार लोग हैरान थे कि जब भाजपा केन्द्र सरकार अपने दम पर चला रही है तो किसी भी कानून को पास कराने में लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर की उपेक्षा क्यों की गई। पार्टी पर बड़े पूंजीपतियों के हित संरक्षण का आरोप लगा और हिन्दुस्तान ने अब तक का सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन देखा लिया। इन पूंजीपतियों को तो बाद में भी फायदा पहुंचाया जा सकता है लेकिन एक बार उत्तर प्रदेश का किला अगर भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल जाने दिया तो फिर यह तथ्य स्थापित हो जाएगा कि तिलिस्म अब टूटने लगा है।

निश्चित रूप से संसार का सबसे बड़ा यह दल नहीं चाहेगा कि ऐसी स्थिति निर्मित हो। इसीलिए बिना कैबिनेट की बैठक बुलाए या दिग्गजों को भरोसे के लिए प्रधानमंत्री ने कृषि कानून वापस लेने की घोषणा कर दी। देर आयद दुरुस्त आयद की कहावत कितनी काम आती है, देखना है। कुछ लोग इसे चुनावी लाचारी भी बता रहे हैं।

बहर हाल आप सल्ललाहु अलैहि व सल्लम ने सैयदना हज़रत अली रजि अल्लाहु अन्हु को अपने घर वालों की ख़बरगोरी के लिए मदीने में छोड़ा। (बुखारी शरीफ 2/633) और कुछ दूसरे हज़रत को ज़िम्मेदार बनाया, और आप जंग के इरादे से तशरीफ ले चले, मदीना मुनब्बरा में माजूरीन और मुनाफ़िकों के अलावा कोई नहीं बचा, जितने भी लोग जा सकते थे वे चले गए।

## अबू ख़ैसमा रज़ि. का जज़बा-ए-हुब्बे रसूल

हज़रत अबू ख़ैसमा रज़ि. अल्लाहु अन्हु हुज़र पाक सल्ललाहु अलैहि व सल्लम के साथ नहीं जा सके थे, एक काम कर के घर वापस आए, तो देखा कि दोनों बीवीयों ने अपने कमरे सजा रखे हैं, छिड़काव कर रखा है, खाना पका रखा है, खुशबू आ रही है, दिल में ख़्याल आया कि अबू ख़ैसमा तो अपनी बीवीयों के साथ मगन हो और पैग़म्बर अलैहिस्सलाम धूल और धूप में तशरीफ ले जा रहे हों, यह इंसाफ़ की बात नहीं है, बीवीयों से कहा कि घर में नहीं आऊँगा, ज़ादे राह तैयार करो, मैं हुज़र के पास जा रहा हूँ, चुनाँचे फौरन ऊँटनी मंगाई और चल दिए, और जाकर पैग़म्बर अलैहिस्सलाम से मिले, दूर से धूल उड़ रही थी, लोगों ने कहा कि कौन आ रहा है? हुज़र ने फरमाया: "कोई न हो यह अबू ख़ैसमा मालूम होते हैं।"

आकर पूरा किस्सा सुनाया, तो पैग़म्बर अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए। (मुस्लिम शरीफ जि. 2 स. 361, ज़ादुल मज़ाद मुकम्मल 736-737)

जहाँ आप तशरीफ़ ले गए, यह तक़रीबन एक महीने की मुसाफ़त थी, आप ने वहाँ जाकर कबाइल से सुलह व मुसालहत कर ली, उनको अपने मातहत कर के जिया नफिज़ कर दिया, इसका असर यह हुआ कि उन रूमियों पर धाक बैठ गई और मुकाबले की नौबत नहीं आई, नबी-ए-अकरम अलैहिस्सलाम वस्सलाम कामियाबी के साथ ख़ैर व आफ़ियत से वापस मदीना मुनब्बरा तशरीफ़ ले आए।

## कअबू बिन मालिक और उनके साथियों का वाकिअ

बुखारी शरीफ़ में एक वाकिअ तफ़सील से बयान किया गया और कुरआन करीम में भी इस का तज़किरा है, इस गज़वे में सब चले गये, मगर तीन सहाबी ऐसे थे जो मुख्लिस थे लेकिन वह जा नहीं पाये, माल व दोलत भी था, सवारियाँ भी थीं, और न जाने की कोई ख़ास वजह भी नहीं थी। (1) हज़रत कअबू बिन मालिक (2) मुरारह बिन रबी (3) हिलाल बिन उम"या रज़ि. अल्लाहु अन्हुमं कोई तो ख़ज़ूँ पकने की वजह से नहीं गया, किसी के यहाँ पोते पड़ पोते सब जमा थे, उनकी वजह से नहीं गया वग़ैरह।

जब पैग़म्बर अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ़ तो आप का दस्तर मुबारक यह था कि पहले मस्जिद तशरीफ़ ले जाते नमाज पढ़ते फिर लोग मुलाक़ात करते उसके बाद घर तशरीफ़ ले जाते। जब हुज़र के आने की ख़बर हुई तो मुनाफ़िकों आकर छूटे सच्चे आज़ार बयान करने लगे लेकिन पैग़म्बर अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ़ कोई तवज़ीह नहीं दी, क्योंकि उन का हिसाब तो अल्लाह तअ़ाला के यहाँ होना है। कअबू बिन मालिक रज़ि. अल्लाहु अन्हु ने फरमाते हैं कि अल्लाह तअ़ाला ने मुझे बोलने का बड़ा सलीक़ा अंता फरमाया था, और शैतान भी मेरे दिल में वसवास डालता रहा कि ऐसी बातें बनाओ कि बात बनी रहे लेकिन जब पैग़म्बर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए तो मेरे दिल को अल्लाह तअ़ाला ने मुतम्मन फरमाया कि अगर तुम कोई गुलत बात कहोगे तो अल्लाह तअ़ाला पैग़म्बर अलैहिस्सलाम को बतला देंगे, इस लिए सच्ची बात के अलावा कोई चारा-ए-कार नहीं है, चुनाँचे हज़रत कअबू बिन मालिक की ख़िदमत में तशरीफ़ लाकर सलाम किया, हज़रत इन्हें देख कर इस तरह मुस्कुराये जैसे कोई नाराज़ आदमी मुस्कुराता है, उन्होंने फरमाया कि हुज़र अगर आप के सामने का मामला न होता तो मैं कुछ न कुछ बात बनाता लेकिन मुझे यकीन है कि अगर मैं कोई गुलत बात कहुंगा तो अल्लाह तअ़ाला आप को बाख़बर कर देंगे, मैं एक मुजरिम बन कर ख़िदमते अक़दस में हाजिर हूँ, आप जो भी सज़ा जारी करें मुझे मंज़ूर है, मेरे पास कोई उज़्ज़ नहीं था, और यह कह कर वापस तशरीफ़ ले आए, लोगों ने कहा कि कुछ बात कह देते बाद में मारी मांग लेते, फरमाया कि नहीं हुज़र से ऐसी बात कहनी मुनासिब नहीं है, मुझे तो सच्ची ही बात कहनी है, हज़रत कअबू बिन मालिक रज़ि. अल्लाहु अन्हु ने लोगों से पूछा कि इस तरह के मामला बाला कोई और भी है? जबाब मिला कि हाँ! मुरारह बिन रबी और हिलाल बिन उम"या हैं, तब कुछ सुकून हुआ कि कम अज़्ज कम तीन आदमी तो हुए।

पैग़म्बर अलैहिस्सलाम ने मदीना मुनब्बरा में ऐलान फरमाया कि इन तीनों आदमियो

# आरजेडी के साथ ने हमको कमज़ोर किया हम खुद का मज़बूत करना भूल ही गए

## तारिक अनवर

**प्रश्न:-** आरजेडी से अलग होकर चुनाव लड़ने का आत्म विश्वास कहां से आया?

**उत्तर:-** आत्मविश्वास नहीं था, मजबूरी थी। जिन दो सीटों के लिए उपचुनाव हुए उनमें से एक सीट आरजेडी की ही हुआ करती थी, एक हमारी थी। हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि उपचुनाव के बहुत आरजेडी कह देगी कि हम आपको एक सीट भी नहीं देंगे। कुशेश्वरस्थान विधानसभा सीट पर 2020 के चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार सिर्फ सात हजार वोट से हारा था। 46 हजार वोट मिले थे हमारे उम्मीदवार को। यह सीट भी हमको नहीं देंगे तो कौन सी सीट देंगे? ठीक है हम बिहार में कमज़ोर हैं लेकिन राष्ट्रीय पार्टी हैं। आरजेडी ने जब हमसे कहा कि हम आपको कोई सीट नहीं देंगे तो हाँ, पर लोग लड़ेंगे।

**प्रश्न:-** एक वर्ष पहले जिस सीट पर आपको 46 हजार वोट मिले थे, उपचुनाव में महज़ 5603 मिले। क्या इसका यह मतलब है कि 46 हजार वोट आरजेडी का शेयर ज्यादा था, जिसे आप अपना समझ रहे थे?

**उत्तर:-** 2020 के चुनाव तक हम लोग गठबंधन में थे। जहां हम लोग लड़ रहे थे, वहां आरजेडी का वोट हमें मिला, जहां आरजेडी लड़ रही थी, उसको हमारा वोट मिला। गठबंधन में इस बात का अलग से कोई आंकलन नहीं हो सकता कि जो वोट मिले, उसमें कितना कितना शेयर घटक दलों का है।

**प्रश्न:-** लेकिन इतना कम वोट मिलना, यह तो साबित करता ही है कि बिहार में आप ज़मीनी स्तर पर नहीं हैं..?

**उत्तर:-** यह सच है कि कांग्रेस

बिहार में दो विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव ने कांग्रेस को उसकी ज़मीनी हक्कीकृत दिखा दी। आरजेडी से अलग होकर चुनाव लड़ते ही दोनों सीटों पर उसने ज़मानत तो गंवाई ही, उसे मिले वोटों की तादाद भी (एक सीट पर महज़ दो प्रतिशत और दूसरी सीट पर 04 प्रतिशत) उसके लिए शर्मिंदगी का सबब बन गई है। आरजेडी से अलग होकर चुनाव लड़ने का 'आत्मविश्वास' कहां से आया और बिहार में अपना वज़द बचाए रखने के लिए क्या कांग्रेस को फिर से आरजेडी की ही शरण में जाना पड़ेगा, इन तमाम प्रश्नों के उत्तर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर ने बड़ी सहजता से दिए, पेश है पिछले दिनों तारिक अनवर जी से हुई एक बातचीत के प्रमुख अंश :-

का जो प्रदर्शन उपचुनाव में रहा है, वह हमारे लिए बहुत बड़ा धक्का है। हमने इतने ख़राब प्रदर्शन की उम्मीद नहीं की थी लेकिन आप चिराग पासवान की पार्टी का प्रदर्शन भी देखिए। उन्हे भी दोनों सीटों पर हमारे जितना वोट मिला है। चुनाव में परसेप्शन का बहुत महत्व होता है। जो धारणा बन जाती है, उससे पार पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उपचुनाव में यह धारणा बन गई कि लड़ाई जेडीयू और आरजेडी के बीच है, इस बजह से वोटों का ध्रुवीकरण

इन्हीं दो पार्टियों के बीच हो गया। दोनों सीटों के रिजल्ट आप देखें 80 से 90 प्रतिशत वोट इन्हीं दो पार्टियों के बीच बट गया।

**प्रश्न:-** अब आगे का क्या एजेंडा तय किया है आप लोगों ने..?

**उत्तर:-** हमें अपने संगठन को मज़बूत करना होगा। मेरी सलाह तो यह रहेगी कि पार्टी नेतृत्व को अपने मूल कार्यकर्ताओं पर भरोसा करना चाहिए और उन्हें ही आगे बढ़ाना चाहिए। राजनीति में बुरे दिन सभी पार्टियों के आते हैं और वे ख़त्म भी होते हैं।

प्रश्न:-

बिहार में कांग्रेस को सत्ता से बाहर हुए 30 वर्ष से ज़्यादा का समय हो गया है। हर चुनाव हारने के बाद हमने कांग्रेस नेताओं को यह कहते सुना है कि हम संगठन को मज़बूत करेंगे लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं, क्यों..?

**उत्तर:-** हमारा आरजेडी के साथ गठबंधन हो गया था। 90 के दशक से बिहार में आरजेडी सबसे मज़बूत दल के रूप में उभरा। आरजेडी के साथ गठबंधन हो जाने पर कांग्रेस

भारत में जमशेद पटेल की स्थितियों के लिए नेतृत्व क्या क़दम उठा सकता है?

**उत्तर:-** दोनों तरह की स्थितियों

के रिजल्ट हमारे सामने हैं। आरजेडी के साथ लड़ने पर भी और उससे अलग होकर लड़ने पर भी। हम तब कहां थे, अब कहां हैं। संगठन को मज़बूत करने के लिए जो भी क़दम ज़रूरी होंगे वे तो उठाए ही जाएंगे। हमारे पास कार्यकर्ता तो हैं लेकिन ज़मीनी कार्यकर्ता नहीं हैं। इस बजह से जनता के बीच में जो समर्थन मिलना चाहिए, वह हमें नहीं मिल पा रहा है। □

## चीन में कम शादियाँ होने व जन्मदर घटने से संकट

भारत में जहां जन्मदर में समानता एक शुभा संकेत माना जा रहा है, और आंकड़े ये बता रहे हैं कि भारत में लिंगापात सही हो गया है, और प्रजनन दर भी कम हो गई है, इन आंकड़ों से सरकार राहत भरी सांस ले रही है वहीं पड़ोसी देश इन आंकड़ों से दुखी है। चीन में जन्मदर लगातार घट रही है जबकि देश में बहुत कम शादियाँ हो रही हैं। इस कारण बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इसके चलते बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इसके चलते दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश इन दिनों जनसांख्यिकीय संकट से गुज़र रहा है। हाल में जारी चाइना स्टैटिस्टिकल ईयरबुक 2021 के आंकड़ों से पता चलता है कि लगातार सात सालों में चीन में विवाह पंजीकरण की संख्या में कमी आई है, जो पिछले वर्ष 17 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। विवाह पंजीकरण में गिरावट को रेखांकित करते हुए जनसांख्यिकीय विशेषज्ञ हे याफू ने कहा -काम के अत्याधिक दबाव, महिला शिक्षा स्तर में सुधार तथा आर्थिक स्वतंत्रता जैसे कारणों से युवाओं में विवाह को लेकर दिलचस्पी घटी है। उन्होंने कहा, एक अन्य प्रमुख कारण महिला-पुरुष आबादी का असंतुलित अनुपात है। चीन में, सातवां राष्ट्रीय जनगणना के अनुसार पुरुषों की संख्या महिलाओं से 3.49 लाख अधिक है। याफू ने कहा कि इनमें विवाह योग्य आयु की महिलाओं की तुलना में 20 वर्ष की आयु में 1.75 लाख अधिक पुरुष है। इसके अलावा बढ़ती महांगाई शादी करने व बच्चे पैदा करने की राह में एक बड़ी बाधा है।

## समीरवानखेड़ की मां के दो डेथ सर्टिफिकेट एक में हिंदू और दूसरे में मुसलमान': नवाब मलिक

नवाब मलिक की मानें तो समीरवानखेड़ की मां जाहिदा की मौत 16 अप्रैल 2015 में हुई थी। उनका पहला डेथ सर्टिफिकेट इसी दिन बनवाया गया था और इस पर इनका धर्म मुस्लिम लिखा गया था। इसके बाद अगले दिन यानी 17 अप्रैल को एक और सर्टिफिकेट भी बनवाया गया जिसमें धर्म को बदलकर हिंदू करवा दिया गया था। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने एनसीबी अधिकारी समीरवानखेड़ पर एक और बड़ा खुलासा किया है। नवाब मलिक ने दावा किया है कि बानखेड़े परिवार ने जाहिदा के दो डेथ सर्टिफिकेट भी बनवाए हैं, एक में वे मुस्लिम हैं जबकि दूसरे में उन्हें हिंदू बना दिया गया है। नवाब मलिक ने समीर की मां जाहिदा का डेथ सर्टिफिकेट भी साझा किया है। नवाब का दावा है कि उनकी मां मुसलमान थी और उन्हें ओशिवारा के कब्रिस्तान में दफनाया गया था। नवाब मलिक की मानें तो समीरवानखेड़ की मां जाहिदा की मौत साल 16 अप्रैल 2015 में हुई थी। उनका पहला डेथ सर्टिफिकेट उसी दिन बनवाया गया था और इस पर इनका धर्म मुस्लिम लिखा गया था। इसके बाद अगले दिन यानी 17 अप्रैल को एक और सर्टिफिकेट भी बनवाया गया जिसमें धर्म को बदलकर हिंदू करवा दिया गया था। बानखेड़े परिवार ने न सिर्फ नैकरी के लिए समीर का धर्म छुपाकर फर्जीवाड़ा किया है बल्कि मां की मौत के बाद भी फर्जीवाड़ा कर दो अलग-अलग दस्तावेज बनवाए थे।

## मेघालय में कांग्रेस के 12 विधायक टीएमसी में शामिल

कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुज़र रही है, कहीं न कहीं उसके उसके साथी उसका साथ छोड़ते चले जा रहे हैं। इसी कड़ी में मेघालय में कांग्रेस के 18 में से 12 विधायकों ने ममता बनर्जी की टीएमसी में शामिल होने का एलान कर दिया। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा भी शामिल हैं। बताया जाता है कि कांग्रेस आलाकमान ने विंसेट पाला को प्रदेश कमेटी का अध्यक्ष बना दिया था। इसे लेकर मुकुल संगमा ने बाबर विरोध जताया था और अब उनकी बात सुनी भी नहीं जा रही थी। इसके साथ ही अब टीएमसी मेघालय में मुख्य विपक्षी दल बन गया है यह कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अब बंगाल के बाद मेघालय ऐसा राज्य बन गया है जहां उसके विधायकों की संख्या बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो गई है। कांग्रेस को इससे दो दिन पहले ही झटका लगा था जब अशोक तंवर और कीर्ति आजाद ने टीएमसी का दामन थाम लिया था।

# नागरिकों पर कोई अपने व्यक्तिगत विचार कैसे थोप सकता है

एक व्यक्ति का भोजन दूसरे व्यक्ति के लिए विष हो सकता है और इस बात का प्रमाण बढ़ती असहिष्णुता के बारे में चल रही बहस है। लव जेहाद से लेकर पाकिस्तान के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन और भारत की बहुलवादी और समावेशी संस्कृति आदि के बारे में विज्ञापन में यह देखने को मिल रहा है। इस पर राष्ट्रव्यापी बहस छिड़ी हुई है हालांकि प्रधानमंत्री मोदी का विचार है कि राष्ट्रीय हित के समक्षा व्यक्तिगत विचारधारा को रखना ग़लत है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव पर तालिबानी मानसिकता का हवाला देते हुए निशाना साधा क्योंकि उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में सरदार पटेल और जिन्ना की तुलना की थी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भारत के खुलेपन, संतुलन और सहिष्णुता को तब तक पर रख दिया जब उन्होंने एक उपभोक्ता वस्तु कंपनी को अपना करवाचौथ विज्ञापन वापस लेने के लिए मजबूर किया, जिसमें प्रगतिशील विवाह का दर्शाया गया था और इस विज्ञापन में एक समलिंगी दंपत्ति थी और इसी तरह एक प्रसिद्ध डिजाइनर के अश्लील मंगल सूत्र डिजाइन की भी आलोचना की गई।

भोपाल में एक वैब-सीरीज की शूटिंग के दौरान एक फिल्म निर्माता पर हमला किया गया। एक बस्त्र ब्रांड पर आरोप लगाया गया कि वह अपने त्यौहारी कलेक्शन को जश्न-ए-रिवाज का नाम देकर दीवाली को बदनाम कर रहा है। एक आभूषण ब्रांड को अपने विज्ञापन को वापस लेने के लिए बाध्य किया गया जिसमें उनकी हिन्दू बहू के लिए मुस्लिम ससुराल में गोद भराई की रस्म दर्शाई जा रही थी।

आशानुरूप भाजपा के कुछ संसदों और बजरंग दल तथा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इन्हें हिन्दू संस्कृति का अपमान बताया तथा हिन्दू त्यौहारों का अहिन्दूकरण कहा। इसके अलावा अनावश्यक रूप से धर्मनिरपेक्षता और मुस्लिम विचार धारा को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग की गई और यह दावा किया गया कि यह उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करता है।

अतः सवाल उठता है कि क्या भारत राजनीतिक असहिष्णुता के युग

की ओर बढ़ रहा है और हिन्दुत्व मूल्यों को लोगों पर थोपा जा रहा है? क्या राजनेता सार्वजनिक जीवन में विचारों के टकराव से डरते हैं? इसलिए पिछले कुछ सालों में यह भावना देखने को मिली है कि उदारवादी चर्चाओं के लिए स्थान सिमटता जा रहा है इस संबंध में हिंसा की घटनाएं, लिचिंग और प्रतिबंध की बातें की जा रही हैं। वर्ष 2015 में 12 फिल्म निर्माताओं और 41 उपन्यासकारों, नाटककारों तथा कवियों ने राष्ट्रीय और साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटा दिए थे और उन्होंने इसका कारण बढ़ती

असहिष्णुता और एक सुप्रसिद्ध तर्कवादी की हत्या पर मौन रहना बताया था।

भारत के बहुलवादी समाज में कभी भी पहले इस तरह का अहसास नहीं हुआ कि हमारा देश धार्मिक ध्रुवीकरण के ख़तरनाक मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, जैसा कि अब देखने को मिल रहा है। हिन्दू वर्चस्वाद और पश्चिमी सांस्कृतिक प्रभाव को तथाकथित रूप से समाप्त करने की भावना बढ़ रही है जिसमें नेताओं द्वारा खड़ी की गई असहिष्णु शक्तियां तर्कवादियों और उदारवादियों को उनकी जगह दिखाने के लिए

प्रतिबद्ध हैं।

पिछले वर्ष के सर्वेक्षण के अनुसार 54 प्रतिशत युवाओं का मानना है कि युवा लोगों में असहिष्णुता बढ़ी है किन्तु 32 प्रतिशत युवा इससे असहमत थे। सामाजिक विद्वेष इंडैक्स के बारे में यू की रिपोर्ट में 198 देशों में भारत को 10 में से 8.7 अंक मिले हैं और वह सीरिया, नाइजीरिया और इराक की श्रेणी में है। उच्चतम न्यायालय ने भी समाज में बढ़ती धर्माधिता पर चिंता व्यक्त की है जिसके परिणामस्वरूप विरोधी मत के बारे में भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार गंभीर

ख़तरे में पड़ गया है। न्यायालय ने एक व्यंग्यात्मक फिल्म के प्रदर्शन की अनुमति न देने पर ममता सरकार पर 20 लाख रुपए जुर्माना लगाया। राजनेता आम आदमी की भावनाओं का दोहन करते हैं और वह कार्य करने का प्रयास करते हैं जिससे उनके बोट बैंक में उनकी लोकप्रियता बढ़े तथा सरकार नज़रअंदाज़ कर इसे बढ़ावा देती है हालांकि यह एक तरह से सांस्कृतिक आतंकवाद और असहिष्णुता है। विरोधाभास देखिए, हिन्दू धर्म विश्व में सबसे सहिष्णु धर्म है फिर भी कुछ नेता और कट्टरवादी तत्व अपनी कट्टरवादी सामाजिक परंपराओं, सांप्रदायिक धृणा, सहिष्णुता को स्वीकार न करना या उनकी तथा उनके धर्म के विपरीत राय और विश्वास का सम्मान करने के बारे में पुरातन पंथी विचारों को बढ़ावा देते हैं और इस संबंध में किसी भी तरह की आलोचना को हिन्दू विरोधी बताते हैं।

कोई मंत्री नागरिकों या राज्य पर अपने व्यक्तिगत विचार कैसे थोप सकता है? कोई व्यक्ति आधिकारिक नामक संकरी पटरी पर जीवन नहीं जा सकता, जहां पर प्रत्येक मज़ाक, व्यंग्य, उपहास या अवज्ञा को एक बड़ा पाप समझा जाता है। सच यह है कि हमने राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त की है किन्तु हम अभी भी समाज के ऐसे तत्वों के बंधक बने हुए हैं। हमें स्वयं-भू गर्जियन नहीं चाहिए जो हमें यह बताए कि हम क्या देख सकते हैं, क्या खा और पी सकते हैं। 'नमो' को अपने पार्टी नेताओं और विशेषकर भाजपा शासित राज्यों में मंत्रियों को कहना होगा कि वे उस प्रत्येक के बारे में संवेदनशील न हो जिन्हें वे सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध मानते हैं और ऐसी प्रत्येक बात को हिन्दू विरोधी और राष्ट्र विरोधी न मानें।

भारत अपने सांस्कृतिक मूल्यों और सांस्कृतिक सहिष्णुता की पुरातन परंपरा के लिए जाना जाता है। भारत ऐसे नेताओं के बिना भी काम चला सकता है जो राजनीति में विकृति पैदा करते हैं और इस विकृति के माध्यम से लोकतंत्र और खुशहाली को नष्ट करते हैं। हमारे नेताओं को समझना होगा कि राष्ट्र की शक्ति इस बात में निहित है कि उसके नागरिक किस तरह से अपने विचारों को स्वतंत्रापूर्वक व्यक्त करते हैं। सरकार की आलोचना देशद्रोह नहीं है। □

## रोज़गार

# हेल्थ केयर इंडस्ट्री सेवा में है सुनहरा भविष्य

पिछले कुछ सालों से लोगों की जीवन शैली में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहे हैं। एक ओर जहां भौतिक सुख-सुविधा के साधनों में बढ़ोत्तरी हो रही है, वहीं दूसरी ओर इसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। नतीजतन, हेल्थकेयर सेक्टर दिन पर दिन गुलज़ार होता जा रहा है। इससे जुड़े कुछ अन्य क्षेत्र में विस्तार प्रक्रिया में हैं। रोज़गार देने के मामले में भी इनका कोई सानी नहीं है। हेल्थकेयर सेक्टर सेवा व समर्पण की भावना से काम करता है। एक डाक्टर का काम जीवन देना होता है, लेकिन इस क्षेत्र में डाक्टरी पेशे के अलावा भी कई ऐसे क्षेत्र हैं, जो जीवन को सुगम बनाते हैं। इनका भी महत्व किसी डाक्टर से कम नहीं होता। देश में मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ हॉस्पिटल एवं क्लीनिक तेजी से खुल रहे हैं। इस इंडस्ट्री के अंतर्गत मेडिकल व पैरामेडिकल से संबंधित कोर्सों की भरमार है। सर्टिफिकेट, डिप्लोमा व डिग्री स्तर के कोर्स छात्रों के सफने को साकार करते हैं। फिजियोथेरेपी, रेडियोग्राफी आदि से संबंधित कई तरह के डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स कराए जाते हैं। डिग्री कोर्स साढ़े चार साल के होते हैं, जबकि डिप्लोमा कोर्स दो साल के। मेडिकल टेक्नोलॉजी व रेडियोग्राफी के लिए तीन साल के स्नातक पाठ्यक्रम मौजूद हैं। मेडिकल ट्रांस्क्रिप्शन के लिए डिप्लोमा कोर्स ज़रूरी है।

**हर तरह के कोर्स मौजूद**  
हेल्थ केयर सेक्टर में पैरामेडिकल से संबंधित कोर्सों की भरमार है। सर्टिफिकेट, डिप्लोमा व डिग्री स्तर के कोर्स छात्रों के सफने को साकार करते हैं। फिजियोथेरेपी, रेडियोग्राफी आदि से संबंधित कई तरह के डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स कराए जाते हैं। डिग्री कोर्स साढ़े चार साल के होते हैं, जबकि डिप्लोमा कोर्स दो साल के। मेडिकल टेक्नोलॉजी व रेडियोग्राफी के लिए तीन साल के स्नातक पाठ्यक्रम मौजूद हैं। मेडिकल ट्रांस्क्रिप्शन के लिए डिप्लोमा कोर्स ज़रूरी है।

**खुद का हुनर परखना ज़रूरी**  
यह प्रोफेशन छात्रों से कई तरह के आवश्यक गुणों की उम्मीद करता है। कुछ अन्य क्षेत्र जैसे मेडिकल एंट्रेंटिव व माइक्रोबायोलॉजी भी इस क्षेत्र की शोभा बढ़ा रहे हैं। कुछ हालिया प्रकाशित रिपोर्ट्स की मानें तो आने वाले समय में पैरामेडिकल क्षेत्र में प्रोफेशनल्स की भारी डिमांड होगी। लगातार कई घंटे तक मरीजों के बीच में रहना होता है। धैर्य भी इस प्रोफेशन का एक खास गुण है, क्योंकि कई बार उन्हें काम के

सिलसिले में अस्पताल व क्लीनिक में देर तक बैठना होता है।  
**व्यापक है इसका कार्यक्षेत्र**  
इस इंडस्ट्री से कई सारे क्षेत्र जुड़े हैं, जिनका अपनी-अपनी जगह पर विशेष महत्व है :-

**फिजियोथेरेपी:-**  
इसमें कई असाध्य अथवा जटिल रोगों का इलाज व व्यायाम या मेडिकल उपकरणों के ज़रूरि किया जाता है। इसके अंतर्गत बॉटर थेरेपी, मसाल आदि को भी शामिल किया जाता है। इसी पूरी प्रक्रिया मनुष्य के शरीर से संबंधित होती है, इसलिए फिजियोथेरेपी को ह्यूमन एनाटोमी, हड्डियों की संरचना, मसल्स एवं नर्वस सिस्टम आदि की जानकारी रखनी पड़ती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंगिलिश सहित बारहवें में 50 परसेंट लाने वाले छात्र इसके डिग्री व डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में दाखिला पा सकते हैं। इसमें ज़्यादातर अवसर हॉस्पिटल पुनर्वास केन्द्र, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट तथा टीचिंग आदि में आते हैं। शुरू में 10,000 से 12,000 रुपए प्रति माह मिलते हैं प्रमुख संस्थान निम्न हैं।

**ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ़ फिजिक्स एंड डिसीन एण्ड रिहाइबिलिटेशन मुम्बई**  
[www.aiipmr.gov.in](http://www.aiipmr.gov.in)  
जामिया हमर्दद फैकल्टी ऑफ़ मेडिसिन, दिल्ली।  
[www.jamiahamedard.edu](http://www.jamiahamedard.edu)

## इस्लामी दुनिया

लाहौर विश्व का सबसे प्रदूषित शहर, स्पॉग और बढ़ा

लाहौर : पाकिस्तान की सांस्कृतिक राजधानी लाहौर के ऊपर धुंध का घने बादल छाए गए हैं नवंबर के मध्य और आखिर में इस शहर के प्रदूषण में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई और इसके साथ ही यह दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया। एक स्विस वायु गुणवत्ता निगरानी कंपनी ने यह जानकारी दी है। आईक्यूएयर मंच ने कहा कि लाहौर प्रदूषित शहरों की उसकी सूचि में सबसे ऊपर है। लाहौर का एक्यूआई 203 जबकि दिल्ली 183 के साथ दूसरे नंबर पर है। कंपनी के अनुसार ढाका (बांग्लादेश) 169 सूचकांक के साथ तीसरे और कोलकाता 168 सूचकांक के साथ चौथे नंबर पर रहा।

## अमेरिकी दखल के बाद यूएई में चीनी निर्माण कार्य रोका

अबू धाबी : अमेरिकी खिफिया एजेंसियों को इस वर्ष यूएई में एक गुप्त चीनी सैन्य ठिकाने पर निर्माण कार्य के सबूत मिले। इसे वाशिंगटन के दखल के बाद अब रोक दिया गया है। वॉल स्ट्रीट जनरल का हवाला देकर पॉलिसी रिसर्च समूह के स्ट्रैटेजिक इनसाइट ने बताया कि खलीफा बंदरगाह पर उपग्रह तस्कीरों की सहायता से चीनी शिपिंग कॉरपोरेशन द्वारा एक कटरेन टर्मिनल में संदिग्ध निर्माण का खुलासा हुआ था। इसके बाद बाइडन ने यूएई के क्राउन प्रिंस से बात की और सबूत दिए।

## पाकिस्तानी तालिबान ने मांगी विदेश में दफ्तर के लिए मंजूरी

इस्लामाबाद: तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) विदेश में राजनीतिक दफ्तर खोलना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने इस मांग को खारिज कर दिया है। यह शांति समझौते के लिए जारी बातचीत के दौरान टीटीपी की ओर से रखी गई तीन मांगों में से एक है। इसके अलावा अन्य मांगों में खेड़बर पख्तुनख्बा के संघ प्रशासित जनजातीय क्षेत्रों (एफएटीए) के विलय रद्द करना और पाकिस्तान में शरिया प्रशासन शामिल है।

## समुद्री ज्वार से म्यांमार में 15 बौद्ध श्रद्धालु मरे

रंगून : म्यांमार के दक्षिणी राज्य मून के थानबिउजैयत में समुद्री ज्वार में बहने से 15 बौद्ध श्रद्धालुओं की मौत हो गई। लोग तट से तीन किमी दूर बीच समुद्र में एक चट्टान पर बने पगोड़ा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। चार मीटर चौड़े कॉर्जवे से हज़ारों लोगों के जाने की कोशिश से यह हादसा हुआ। पगोड़ा तक जाने को अस्थायी पुल पार करने के लिए कारण बौद्ध श्रद्धालु इस दुर्घटना के शिकार हुए।

# आज फिर नेहरू और पटेल की ज़रूरत

मेरे गृह नगर बंगलूरु में सेकंड हैंड किताबों की देश की सबसे अच्छी दुकानें मौजूद हैं। दशकों से ये दुकानें मेरी निजी और पेशेगत ज़रूरतें पूरी करती आई हैं, जहां से मुझे सोने से पहले पढ़ी जाने वाली सामग्री से लेकर मेरे अनुसंधान से संबंधित दुर्लभ दस्तावेज़ मिलते रहे हैं।

पिछले दिनों मैंने ऐसी ही एक दुकान से एक पुरानी किताब हासिल की, जो कि मेरे दोनों ही मक्सद को पूरी करती थी। यह किताब है : 1950 में प्रकाशित ए.एस. आयंगर की 'ऑल थ्रू द गांधियन इरा' एक पत्रकार के रूप में आयंगर ने चेम्सफोर्ड और उनके बाद के सभी वायसराय का इंटरव्यू किया था और राष्ट्रीय आदोलन के बड़े नेताओं के साथ उनकी प्रायः घनिष्ठता थी। उनकी किताब में उनके साथी पत्रकारों के जीवनवृत्त दिए गए हैं और उसके साथ ही उसमें असहयोग आदोलन, 1930-40 के दशकों की सांप्रदायिक राजनीति तथा दूसरे विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव पर केन्द्रित अध्याय है।

'ऑल थ्रू द गांधियन इरा' के अध्याय का शीर्षक है, नेहरू और पटेल! इन दोनों स्वतंत्रता संग्राम के दौर में काम करते हुए और फिर उन्हें प्रधानमंत्री और उपप्रधानमंत्री के रूप में काम करते हुए देख रहे आयंगर ने टिप्पणी की 'यह देश का सौभाग्य है कि हमारे पास पंडित नेहरू और सरदार पटेल के रूप में दो ऐसे व्यक्तित्व हैं, जिनमें ऐसे गुण हैं जो कि एक दूसरे के लिए पूरक जैसे हैं।' इसके बाद वह लिखते हैं कि 'मनुष्यों और यथार्थ का ऐसा युग्म कहीं और देखने को नहीं मिलता, जैसी पूर्णता जवाहरलाल नेहरू और बल्लभ भाई पटेल में है।'

आयंगर ने इन दो राष्ट्रीय निर्माताओं के काम को व्यक्त करने के लिए 1950 में एक ऐसे रूपक का इस्तेमाल किया, जो कि पहले ही भारत के सबसे लोकप्रिय खेल में प्रयुक्त हो रहा था। उन्होंने टिप्पणी की, 'ये दोनों क्लीन फाइटर हैं और नेहरू को जहां छक्के जड़ना पसंद है, वहाँ पटेल एक शानदार बल्लेबाज़ है, जो कि गेंदबाज़ को थकाकर अच्छा स्कोर खड़ा कर देते हैं।' उनका अगला रूपक दुनिया के सबसे महंगे खनिज से जुड़ा है। जैसा कि उन्होंने लिखा 'ये दोनों हीरे की तरह है, उनमें अंतर है तो यह कि जहां सरदार बिना तराशा हुआ हीरा है, वहाँ नेहरू एक फिनिश ग्रोडकर है, जिसके फलक तराशे हुए हैं और

इसलिए वह चमकदार लगते हैं।

हाल के सालों में विचारकों ने व्यक्तित्व के इस अंतर को गहरी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में बदल दिया। नेहरूवादी परोक्ष रूप से जताते हैं कि पटेल गुप्त तरीके से सांप्रदायिक थे, पटेलवादी नेहरू पर विदेश नीति से संबंधित अनेक गलतियां करने के आरोप लगते हैं। ये पक्षपाती यह भी दावा करते हैं कि ये दोनों वास्तव में एक दूसरे पर अविश्वास करते थे।

गोपालकृष्ण गांधी ने नेहरू-पटेल की जुगलबंदी की गलत व्याख्या को लेकर रेखांकित किया है इस मामले में भारत के दो बड़े राजनीतिक दलों

ए.एस. आयंगर ने इन दोनों शर्खियत के रिश्ते के गहन अध्ययन के आधार पर जो लिखा है, उससे इन दोनों के बीच की कथित प्रतिद्वंद्विता की परतें उघड़ जाती हैं। उन्होंने 1947-50 के उन महत्वपूर्ण सालों पर अपना अध्ययन केन्द्रित किया है, जब नेहरू और पटेल एक बिखरे और विभाजित देशकों जोड़ने के लिए एक साथ काम कर रहे थे। उन्होंने 1947-50 के उन महत्वपूर्ण सालों पर अपना अध्ययन केन्द्रित किया है, जब नेहरू और पटेल एक बिखरे और विभाजित देशकों जोड़ने के लिए एक साथ काम कर रहे थे। उन्होंने लिखा 'परस्पर एक दूसरे को सहयोग करने वाले, न कि विरोधाभासी, गुणों के जरिये नेहरू और पटेल न केवल देश के समक्ष आई समस्याओं को सुलझा रहे हैं, बल्कि लगातार बढ़ती जा रही चुनौतियों का भी सामना कर रहे हैं।

की मिलीभगत है। पहले कांग्रेस ने पटेल का परित्याग किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने गृहत तरीके से उन्हें अपनाया। दुर्भाग्य से पटेल की जयंती ठीक उसी दिन होती है, जिस दिन इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। 1985 से जब तक कांग्रेस सत्ता में रही, उसने पूरे उत्साह के साथ 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया और वह जनता को यह बताना भूल गई कि इसी दिन पटेल का जन्म भी हुआ था।

चूँकि नेहरू-गांधी परिवार ने पटेल की प्रशस्ति नहीं की, इसलिए भाजपा

ने यह काम किया। यह बहुत अजीब है। पिछले आम चुनाव के दौरान यह गलत तरीके से प्रचारित किया गया कि नेहरू दिसम्बर, 1950 में पटेल की अंत्येष्टि में शामिल नहीं हुए थे।

ए.एस. आयंगर ने इन दोनों शर्खियत के रिश्ते के गहन अध्ययन के आधार पर जो लिखा है, उससे इन दोनों के बीच की कथित प्रतिद्वंद्विता की परतें उघड़ जाती हैं। उन्होंने लिखा 'परस्पर एक दूसरे को सहयोग करने वाले, न कि विरोधाभासी, गुणों के जरिये नेहरू और पटेल एक बिखरे और विभाजित देशकों जोड़ने के लिए एक साथ काम कर रहे थे। उन्होंने लिखा 'परस्पर एक दूसरे को सहयोग करने वाले, न कि विरोधाभासी, गुणों के जरिये नेहरू और पटेल एक बिखरे और विभाजित देशकों जोड़ने के लिए एक साथ काम कर रहे थे। उन्होंने लिखा 'परस्पर एक दूसरे को सहयोग करने वाले, न कि विरोधाभासी, गुणों के जरिये नेहरू और पटेल न केवल देश के समक्ष आई समस्याओं को सुलझा रहे हैं, बल्कि लगातार बढ़ती जा रही चुनौतियों का भी सामना कर रहे हैं।

पंडित नेहरू ने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि एक दिन भी ऐसा

नहीं बीतता, जब वह सरदार पटेल से नहीं मिलते और उनके साथ नीति

और प्रशासन से संबंधित मुद्दों पर

उनके साथ विचार विमर्श नहीं करते।

इसी तरह से, सरदार पटेल भी प्रध

नमंत्री से सलाह किए बिना कोई

बढ़ा निर्णय नहीं लेते। यह युग्म देश की प्रगति के लिए बहुत उपयोगी है, बेशक राजनेताओं के एक वर्ग को यह नहीं सुहा रहा है।

ऐसा अब भी है! इसी बजह से इंदिरा गांधी और उनके बंशजों ने पटेल के योगदान को दबा दिया, जबकि नरेन्द्र मोदी और भाजपा ने दो ऐसे भारतीयों के बीच पक्षपाती तरीके से विरोध पैदा कर दिया है, जिन्होंने देश के निर्माण के लिए एक साथ मिलकर काम किया था।

आयंगर ने नेहरू को दूरदृष्टा और सैद्धांतिक बताया, तो पटेल को व्यवहारिक और यथार्थवादी। नवजात भारत को दोनों तरह के व्यक्तियों की ज़रूरत थी, बल्कि तय यह है कि इंदिरा गांधी की प्रतिद्वंद्विता की परतें उघड़ जाती हैं। उन्होंने 1947-50 के उन महत्वपूर्ण सालों पर अपना अध्ययन केन्द्रित किया है, जब नेहरू और पटेल एक बिखरे और विभाजित देशकों जोड़ने के लिए एक साथ काम कर रहे थे। उन्होंने लिखा 'परस्पर एक दूसरे को सहयोग करने वाले, न कि विरोधाभासी, गुणों के जरिये नेहरू और पटेल न केवल देश के समक्ष आई समस्याओं को सुलझा रहे हैं, बल्कि लगातार बढ़ती जा रही चुनौतियों का भी सामना कर रहे हैं।

लिखा 'परस्पर एक दूसरे को सहयोग करने वाले, न कि विरोधाभासी, गुणों के जरिये नेहरू और पटेल न केवल देश के समक्ष आई समस्याओं को सुलझा रहे हैं, बल्कि लगातार बढ़ती जा रही चुनौतियों का भी सामना कर रहे हैं।

लिखा 'परस्पर एक दूसरे को सहयोग करने वाले, न कि विरोधाभासी, गुणों के जरिये नेहरू और पटेल न केवल देश के समक्ष आई समस्याओं को सुलझा रहे हैं, बल्कि लगातार बढ़ती जा रही चुनौतियों का भी सामना कर रहे हैं।

लिखा 'परस्पर एक दूसरे को सहयोग करने वाले, न कि विरोधाभासी, गुणों के जरिये नेहरू और पटेल न केवल देश के समक्ष आई समस्याओं को सुलझा रहे हैं, बल्कि लगातार बढ़ती जा रही चुनौतियों

# भारत में भ्रष्टाचार का फैलना नासुर

रवि शंकर

भ्रष्टाचार एक ऐसी समस्या है, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। सरकार भले कालेधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ़ सख्त हो, लेकिन देश में अब भी लोग अपना काम कराने के लिए रिश्वत देने को मजबूर हैं। यह खुलासा भ्रष्टाचार पर निगाह रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा भ्रष्टाचार ख़त्म करने के दावों के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब उन्तालीस प्रतिशत लोगों को अपना काम कराने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। यह एशिया के साथ कंबोडिया दूसरे और तीस प्रतिशत के साथ इंडोनेशिया तीसरे स्थान पर हैं नेपाल में यह दर बारह प्रतिशत, बांग्लादेश में चौबीस और चीन में 28 प्रतिशत पाई गई।

एशिया में सबसे ईमानदार देशों के बारे में बात करें तो मालदीव और जापान में सिर्फ दो प्रतिशत लोग मानते हैं कि उन्हें रिश्वत देनी पड़ी। तीसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया है। इस हिसाब से घूसखोरी के मामले में भारत का एशिया में प्रथम स्थान है। सर्वे में सरकारी कर्मचारियों में पुलिसकर्मियों को सबसे ज्यादा भ्रष्ट पाया गया। छियालीस प्रतिशत लोगों ने माना कि पुलिस सबसे ज्यादा भ्रष्ट हैं इसके अलावा बयालीस प्रतिशत का मानना है कि संसद भ्रष्ट हैं। इकतालीस प्रतिशत लोगों को लगता है कि सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार है। बीस प्रतिशत लोगों ने कहा है कि जज और मजिस्ट्रेट भी भ्रष्ट हैं।

इस रिपोर्ट में देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को अलग-अलग श्रेणी में रखा गया है। जैसे नवासी प्रतिशत भारतीय सरकारी भ्रष्टाचार को सबसे बड़ी समस्या मानते हैं। इसके बाद उनतालीस प्रतिशत रिश्वतखोरी को बड़ी समस्या मानते हैं, जबकि छियालीस प्रतिशत किसी भी चीज़ के लिए सिफारिश किए जाने को समस्या मानते हैं। अठारह प्रतिशत

भारतीय एस भा है, जो मानत है कि वोट के लिए नोट एक बड़ी समस्या है। वहाँ ग्यारह प्रतिशत ने माना कि काम निकलवाने के लिए होने वाली शारीरिक शोषण एक बड़ी समस्या हैं देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर

ज्यादातर भारतीयों की आम राय है कि बीते एक वर्ष में यह बढ़ा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार के खिलाफ़ काम करने वाली संस्था है। यह 2003 से हर वर्ष भ्रष्टाचार पर रिपोर्ट जारी कर रही है। विभिन्न संगठनों के संघर्ष के बाद भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए 12 अक्टूबर 2005 को देश में सूचना का अधिकार कानून भी लागू किया गया। इसके बावजूद रिश्वतखोरी कम नहीं हुई। बहरहाल, आज पूरी दुनिया में सार्वजनिक क्षेत्र, विशेषकर राजनीतिक दलों, पुलिस और न्यायिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार दुनिया के लिए बड़ी चुनौती है। दुनिया में सत्ता का दुरुपयोग, गोपनीय सौदेबाज़ी और रिश्वतखोरी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से दुनियाभर के समाज बर्बाद हो रहे हैं। भारत भी इससे अछूत नहीं है।

यह गहरे आत्ममंथन का विषय है कि हाल के सालों में भ्रष्टाचार के खिलाफ़ बड़े पैमाने पर जनभावना उभरने के बावजूद वास्तविक स्थिति में सुधार क्यों नहीं हुआ? बता दें कि यह सूचकांक तैयार करते समय सरकारी क्षेत्र में भ्रष्टाचार को लेकर विशेषज्ञों की राय पर गैर किया जाता है। बहरहाल, आज भारत में भ्रष्टाचार अपनी जड़ें फैला रहा है, और इसके कई रूप हैं, जैसे रिश्वत, काला बाज़ारी, जानबूझ कर दाम बढ़ाना, पेसा लेकर काम करना, सस्ता सामान लाकर महंगा बेचना आदि। समस्या यह है कि अब भ्रष्टाचार हमारी आदत में शामिल हो गया है। ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल भारत के बारे में हर साल कहता है कि देश के आधे से ज्यादा लोग (उनमें बच्चे भी शामिल हैं) यह जानते हैं कि भ्रष्टाचार क्या होता है और कैसे किया जाता है? खैर, कलंक हमारा है और मुक्त करने का तरीका भी हमें ही खोजना है।

भ्रष्टाचार के इस रोग के कारण हमारे देश का कितना नुकसान हो रहा है, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। पर इतना तो साफ दिखता है कि सरकार द्वारा चलाई गई अनेक योजनाओं का लाभ लक्षित समूह तक नहीं पहुंच पाता। इसके लिए सरकारी तंत्र के अलावा जनता भी दोषी है। यों कहें कि भ्रष्टाचार से देश की अर्थव्यवस्था और प्रत्येक व्यक्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कायदे से भारत सरकार को यह आंकलन करना चाहिए कि देश में भ्रष्टाचार घट रहा है या बढ़ रहा है और उसी के अनुरूप क़दम उठाने चाहिए, लेकिन वह ऐसा नहीं करती।

आजादी के एक दशक बाद से ही भारत भ्रष्टाचार के दलदल में धंसा नज़र आने लगा था और उस समय संसद में इस बात पर बहस भी होती थी। 21 दिसंबर, 1963 को भारत में भ्रष्टाचार के खात्मे के

लिए संसद में बहस में डॉ. राममनोहर लोहिया ने कहा था कि सिंहासन और व्यापार के बीच संबंध भारत में जितना दृष्टिभ्रष्टा और बेर्इमान हो गया है उतना दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ है। प्रश्न है कि भारत जब दुनिया का एक सभ्य और आदर्श लोकतांत्रिक देश है, तो यहां भ्रष्टाचार क्यों नहीं घट रहा है? एक सफल देश का मतलब यह होना चाहिए कि वहां भ्रष्टाचार न हो। हालांकि सफलता का पैमाना केवल आर्थिक आंकड़े नहीं है। सामाजिक विकास का पैमाना केवल धन-संपदा नहीं है, असली सामाजिक आर्थिक विकास तो हम उसे ही कहेंगे, जहां भ्रष्टाचार की गुंजाइश न हो। भ्रष्टाचार अगर बना रहा, तो विकास के हमारे सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। यदि भारत के राजनीतिक सामाजिक माहौल की

www.ijerpi.org | 2023, Vol. 11, No. 1 | ISSN: 2227-4324 | DOI: 10.5281/zenodo.750022

मुक्ति पाने का इंतज़ाम करें। पहले भ्रष्टाचार के लिए परमिट लाइसेंस राज को दोष दिया जाता था, पर जब से देश में वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, विदेशीकरण, बाजारीकरण और विनियमन की नीतियाँ आई हैं, तबसे घोटालों की बाढ़ आ गई है। इन्हीं के साथ बाजारवाद, भोगवाद, विलासिता तथा उपभोक्ता संस्कृति का भी ज़बरदस्त हमला शुरू हुआ है। हालांकि भ्रष्टाचार निपटने के लिए सरकारी स्तर पर भी तमाम दावे करके औपचारिकता पूरी कर ली जाती है, लेकिन नतीजा वही ढांक के तीन पात रहता है। अब तो हालत यह हो गई है कि हमारा देश भ्रष्टाचार के मामले में भी लगातार तरक्की कर रहा है। प्रधानमंत्री भी मानते हैं कि मौजूदा समय में देश में भ्रष्टाचार और गरीबी बढ़ी समस्याएं हैं। हकीक़त में जनता के कल्याण के लिए शुरू की गई तमाम योजनाओं का फायदा नेता और नौकरशाह ही उठाते हैं। आखिर में जनता ठगी रह जाती है। शायद यही उसकी नियति है। यह सच है कि भारत महाशक्ति बनने के करीब है, पर हम भ्रष्टाचार की वजह से इससे दूर होते जा रहे हैं।

भारत सरकार के साथ-साथ देश की सिविल सोसायटी और आमजन के लिए भी यह गहरे आत्मगमनथन का विषय है कि हाल के सालों में भ्रष्टाचार के खिलाफ़ बढ़े पैमाने पर जनभावना उभरने के बावजूद वास्तविक स्थिति में सुधार क्यों नहीं हुआ? बता दें कि यह सूचकांक तैयार करते समय सरकारी क्षेत्र में भ्रष्टाचार को लेकर विशेषज्ञों की राय पर गैर किया जाता है। बहरहाल, आज भारत में भ्रष्टाचार अपनी जड़ें फैला रहा है, और इसके कई रूप हैं, जैसे रिश्वत, काला बाज़ारी, जानबूझ कर दाम बढ़ाना, पेसा लेकर काम करना, सस्ता सामान लाकर महंगा बेचना आदि। समस्या यह है कि अब भ्रष्टाचार हमारी आदत में शामिल हो गया है। ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल भारत के बारे में हर साल कहता है कि देश के आधे से ज्यादा लोग (उनमें बच्चे भी शामिल हैं) यह जानते हैं कि भ्रष्टाचार क्या होता है और कैसे किया जाता है? खैर, कलंक हमारा है और मुक्त करने का तरीका भी हमें ही खोजना है।

# ख़ास ख़बरें

## चीन की बढ़ती ताक़त स्वतंत्र समुद्र के लिए ख़तरा

हैलीफैक्स : अमेरिकी हिंद प्रशांत नौसेनिक कमान के शीर्ष कमांडर एडमिरल जॉन सी एक्विलिनो ने चीन की बढ़ती सैन्य ताक़त को मुक्त समुद्र के लिए खतरा करार दिया। उन्होंने इस क्षेत्र में चीन की सैन्य गतिविधियों के खिलाफ़ तत्काल कदम उठाने ज़रूरत बताई। इंटरनेशनल सुरक्षा फोरम में एडमिरल ने कहा, राष्ट्रपति शी जिनपिंग चीनी सेना को 2927 तक अमेरिका की सेना के बराबर बनाना चाहते हैं।

**कोविड पार्बंदियों के  
खिलाफ़ नीदरलैंड के  
बाद यूरोप के दूसरे दूशों  
में भी हिंसा**

एम्स्टर्डम : पिछले दिनों कोविड प्रतिबंधों के खिलाफ़ नीदरलैण्ड से शुरू हिंसक प्रदर्शन इटली, आस्ट्रिया, बेल्जियम, फ्रांस और क्रोएशिया समेत कई यूरोपीय देशों में भी फैल गया था। नीदरलैण्ड में रॉटरडम के बाद इन शहरों में हिंसा और आगजनी हुई। सरकार ने संक्रमण की रफ्तार रोकने के लिए प्रतिबंधों की घोषणा की थी। विएयना में 10 हजार से ज्यादा लोगों ने प्रदर्शन किए।

## लिथुआनिया से चीन ने रिश्ते किए सीमित

**बीजिंग :** लिथुआनिया में ताइवान के दूतावास खोलने से नाराज़ चीन ने लिथुआनिया से अपने राजनयिक संबंधों को सीमित करते हुए राजदूत की जगह चीफ ऑफ मिशन के स्तर का कर दिया। इससे पहले चीन ने लिथुआनिया के राजदूत को बीजिंग से निष्कासित कर दिया था और अपने

राजदूत का भी वापस बुला लिया था।  
**अमेरिका में अब बच्चों  
को तेजी से शिकार बना  
रहा कोरोना वायरस**

**वाशिंगटन :** कोरेना महामारी से बुरी तरह प्रभावित अमेरिकी में वायरस अब तेजी से बच्चों को अपना शिकार बनाने लगा है। वायरस का यह रूप दुनिया के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स (एएपी) की रिपोर्ट के अनुसार बीते दिनों 11 से 18 नवंबर के बीच 1,41,905 बच्चों में संक्रमण की पुष्टि हुई। रिपोर्ट के अनुसार बच्चों में संक्रमण की गति बीते दो सप्ताह की तुलना में 32 फीसदी की बढ़ोत्तरी दर्ज हुई है। अनुमान के अनुसार लगभग 68 लाख से अधिक बच्चे संक्रमण की चपेट में आ चके हैं।

## प्रज्ञा ठाकुर मुंबई की अदालत में पेशी

महाराष्ट्र के मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी भाजपा की भोपाज से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की विशेष अदालत में पेश हुई।

# अतबा बिन रबीअहा के दिल पर कुरआन का प्रभाव<sup>2</sup>

ज़रिए से हकूमत चाहते हो तो हम तुम्हें अपना बादशाह, हाकिम बना लेते हैं। यह तो तुम्हारे पास आता है अगर कोई “रह” यानि जिन्नाती असर है जिसे तुम देखते हो और अपने पास से दूर करने की कुदरत नहीं रखते तो हम तुम्हारे लिए झाड़-फूंक का इंतज़ाम करेंगे और हम इसके लिए अपना माल खर्च करके उससे तुम्हें निजात (छुटकारा) दिलाएंगे, क्योंकि कभी-कभी मोक्षकल या जिन्न आदमी पर जमा लेता है तो उसका ईलाज किए बगैर नहीं जाता। यही शब्द या इसी प्रकार के वाक्य उसने आप (सल्लू) से कहे।

रसूलुल्लाह (सल्लू) उसकी बातें सुनते रहे और जब अतबा अपनी बातचीत ख़त्म कर चुका तो आपने फरमाया “ऐ अबू अल वलीद! तुझे जो कुछ कहना था वह कह चुका? कहा हां - फरमाया : अब मुझ से सुन, बोला :-सुनाईये! रसूलुल्लाह (सल्लू) ने उसके सामने कुरआन मजीद का वह हिस्सा तिलावत फरमाया जिसका अनुवाद यह है। “शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, अत्यधिक रहमत वाला है। यह किताब उतारी हुई है बड़े मेहरबान निहायत रहम वाले अल्लाह तथाला की ओर से! यह कुरआन ऐसी मुफस्सिल, वाज़े और अज़ीम किताब है जिसकी आयतों की पूरी वज़ाहत के साथ तपसील की गयी है। इस हाल में कि यह कुरआन अरबी भाषा में है इस कौम के लिए जो जानती है और यह कुरआन खुशख़बरी सुनाने वाला और डराने वाला है। फिर भी उनकी अकसरियत ने मुंह फेर लिया

और वह सुनते ही नहीं और उन्होंने कहा कि तू जिसकी तरफ हमें बुला रहा है। हमारे दिल तो उस से पर्दे में हैं और हमारे कानों में इससे गिरानी और बेहरापन है और हम में और तुझ में एक हिजाब है। अच्छा तू अपना काम किए जा, हम भी यकीनन काम करने वाले हैं (सज्दा)। फिर रसूलुल्लाह (सल्लू) इसी सूरत को और आगे पढ़ते चले गए। अतबा खामोश सुनता रहा उसने हाथ पीछे रख लिए और उनसे सहारा लिए हुए था इसके बाद रसूलुल्लाह (सल्लू) सज्दे तक पहुंचे तो सज्दा किया, फिर

**जब वह उनके पास जाकर बैठा तो उन्होंने कहा “ऐ अबू अल वलीद, वहां की क्या ख़बर है? उसने कहा : वहां की ख़बर यह है कि मैंने ऐसा कलाम सुना है कि वल्लाह मैंने ऐसा प्रभावी कलाम कभी नहीं सुना वल्लाह वह न शेर है न जादू और न कहानत! ऐ कुरैश के लोगों! मेरी बात सुनों और इस काम को मेरी राय के अनुसार करो। इन (मौहम्मद (सल्लू)) को उनके हाल पर छोड़ दो और उनसे अलग रहो क्योंकि वल्लाह उनकी जो बात मैंने सुनी है उसे बड़ी अहमियत हासिल होगी। अगर अरबों ने उनका खात्मा कर दिया तो समझ लेना उन्होंने तुम्हें इससे बेनियाज़ कर दिया। और अगर उन्होंने अरबों पर प्रभाव प्राप्त कर लिया तो उनकी हुकूमत तुम्हारी हुकूमत और उनकी इज़्जत तुम्हारी इज़्जत होगी। तुम उनके तुफैल सारे लोगों में सबसे ज़्यादा खुशहाल और खुशनसीब हो जाओगे। उन लोगों ने कहा : “ऐ अबू अल वलीद, वल्लाह उसने तुम पर भी अपनी जुबान का जादू कर दिया। अतबा ने जवाब दिया : मेरी राय तो उनके संबंध से यही है अब तुम्हारी मर्जी है जो चाहे करो।**

यानि कुरआन की बात उसके दिल में उतरी लेकिन हिदायत उसी को मिलती है जिसको अल्लाह तथाला हिदायत देना चाहे। इसलिए जब आपके चचा अबू तालिब बावजूद आपकी सदाक़त का यकीन रखते हुए भी बाप-दादा की तकलीद (लीग को मानना) पर चलते हुए आप (सल्लू) की तसल्ली के लिए फरमाया, अनुवाद “ऐ, हमारे नबी मौहम्मद (सल्लू) बेशक आप जिसको चाहें हिदायत नहीं दे सकते लेकिन अल्लाह तथाला जिसको चाहता है हिदायत देता है और वह हिदायत पाने वालों और हिदायत के पात्र लोगों को अच्छी तरह से जानता है (इसलिए आप की दावत देने के बावजूद जब कोई इस्लाम न लाए तो उसका आप अधिक ग़म न करें। □□

## मुस्तफ़ा (स.) के कूचे में

-अजमल सुलतानपुरी

जेरे सायए गुंबद शाम का बसेरा है और सुनहरी जाली पर रुनुमा सवेरा है

जा बजा मदीने में हाजियों का डेरा है मुस्तफ़ा के कूचे में साएलो का फेरा है या नबी मदद कीजे उलझनों ने घेरा है अब तो मेरी राहों में दूर तक अंधेरा है

काश हश के दिन मैं इस तरह उठूं या रब खुद हुजूर फरमाएं यह गुलाम मेरा है कारवां से बिछड़ा हूं जा रहा हूं तैबा को जुअफ़ का यह आलम है हर क़दम पे डेरा है

क़ब्र में फरिश्तों से आपने यह फरमाया जाओ इसको सोने दो उम्मती यह मेरा है देखने की ख़ाहिश है उस सुनहरी जाली को जिस पे रहमते हक़ ने नूर को बिखेरा है नअ्ते मुस्तफ़ा ‘अजमल’ शौक़ दिल से पढ़ता चल फिर तो सारी दुनिया में जो भी है वो तेरा है

## ﴿كُوْرَيْهُ كُوْرُوكُونِيَا﴾

(सूरा अत्तकासुर नं० 102)

अनुवाद और व्याख्या : शैखुल हिन्द र.अ.

यह सूरा मक्का में उतरी इसमें 8 आयतें हैं।

प्रारंभ करता हूं मैं अल्लाह के नाम से जो असीम कृपालु महादयालु है।

तुमको अधिकता के लालच ने ग़फ़्लत (बेख़बरी) में रखा यहां तक कि तुमने कब्रें जा देखीं।

अर्थात् माल और औलाद की अधिकता और दुनिया के धन संपत्ति का लालच आदमी को ग़फ़्लत में फ़ंसाये रखता है न मालिक का ध्यान आने देता है और न आखिरत का। बस रात-दिन यही धुन लगी रहती है कि जिस प्रकार हो सके माल-दौलत की अधिकता हो और मेरा कुनबा (परिवार) और जत्था सब कुनबों और जत्थों पर विजयी रहे। यह ग़फ़्लत (बेख़बरी) का पर्दा नहीं उठता, यहां तक कि मौत आ जाती है तब कब्र में जाकर पता लगता है कि सख़्त ग़फ़्लत और भूल में पड़ा हुआ था। केवल कुछ दिनों की चहल-पहल थी। मौत के पश्चात् वह सब सामान बेकार और बबाल है।

**चेतावनी** :-कुछ हदीसों में आया है कि हर बार दो कबीले अपने-अपने जत्थों की संख्या की अधिकता पर घमंड कर रहे थे। जब मुक़ाबले के समय एक के आदमी दूसरे से कम रहे, तो उसने कहा - हमारे इतने आदमी लड़ाई में मारे जा चुके हैं, चलकर कब्रें गिन लो। वहां पता लगेगा कि हमारा जत्था तुम से कितना बड़ा है और हम में कैसे-कैसे नाम वाले गुज़र चुके हैं। यह कहकर कब्रें गिनने लगे। इस मूर्खता और ग़फ़्लत पर चेतावनी देने के लिए यह सूरा उतरी।

**कदापि** नहीं तुमको बहुत शीघ्र ज्ञात हो जायेगा, फिर कदापि नहीं तुमको बहुत शीघ्र ज्ञात हो जायेगा।

अर्थात् देखो बार-बार चेतावनी देकर कहा जाता है कि तुम्हारा ख़्याल ठीक नहीं कि माल औलाद आदि की बहुलता ही काम आने वाली वस्तु है, निकट भविष्य में जान लोगे कि यह मिट्टे वाली वस्तु कदाचित घमंड करने योग्य नहीं थी। फिर समझ लो कि आखिरत ऐसी चीज़ नहीं जिससे इंकार किया जाये या उदासीनता बरती जाये। आगे चलकर तुमको बहुत शीघ्र खुल जायेगा कि वास्तविक जीवन और आनंद आखिरत का है और दुनिया उस जीवन के मुक़ाबले में एक सपने से अधिक वास्तविक नहीं रखती। यह वास्तविकता कुछ लोगों पर दुनिया में थोड़ी खुल जाती है, लेकिन कब्र में पहुंच कर और उसके पश्चात् मैदाने हश्र में सबको स्पष्ट रूप से पता चल जायेगा।

**कदापि** नहीं यदि तुम विश्वसनीय रूप से जान लते (तो कभी इस बेख़बरी में न पड़े रहते)?

अर्थात् तुम्हारा ख़्याल ठीक नहीं, अगर तुम विश्वासपूर्वक सच्ची दलील से इस बात को जान लेते और मान लेते कि आखिरत के मुक़ाबले में दुनिया के सब सामान तुच्छ हैं, तो कभी भी इस ग़फ़्लत में पड़े न रहते।

**निःसंदेह** तुमको अवश्य दोज़ख़ को देखना है फिर **निःसंदेह** उसको विश्वास की आंख से देखना है।

अर्थात् इस ग़फ़्लत और इंकार का परिणाम दोज़ख़ है। वह तुमको देखना पड़ेगा। प्रथम बार तो उसका कुछ प्रभाव बज़र्ख़ (मौत के बाद क़्यामत तक का समय) में नज़र आ जायेगा। फिर आखिरत में पूर्ण रूप से देखकर पक्का विश्वास हो जायेगा।

रुकू नं० 1

फिर तुमसे उस दिन आराम की वास्तविकता पूछेंगे।

अर्थात् उस समय कहेंगे, अब बतलाओ दुनिया के ऐश व आराम की क्या वास्तविकता थी या प्रश्न किया जायेगा कि जो नामतें दुनियां में दी गई थीं उनका हक़ तुमने क्या अदा किया और अल्लाह को कहां तक प्रसन्न रखने का प्रयत्न किया।

हज़रत मुहम्मद सल्लू ने फरमाया - क़्यामत के दिन कोई भी व्यक्ति जब तक पांच प्रश्नों का जवाब न देगा, अपनी जगह से सरक नहीं सकता।

(1) अपनी उम्र किन कामों में व्यतीत की।

(2) अपनी जवानी कहां-कहां ख़र्च की।

(3) माल कैसे-कैसे किया, जायज़ या नाजायज़।

(4) उसको कहां-कहां ख़र्च किया, जायज़ या नाजायज़।

(5) अल्लाह ने जो इलम दिया था उस पर कितना अमल किया।

दूसरी हदीस में है कि क़्यामत के रोज़ बंदे से सबसे पहले स्वास्थ्य के संबंध में प्रश्न होगा।

# कथा योगी इतिहास दोहरा सकेंगे?

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में अब यह साफ है कि मुख्य मुकाबला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच होने जा रहा है। दोनों यानि भाजपा और समाजवादी पार्टी ने अपने-अपने सहयोगी दल चिह्नित भी कर लिए हैं और गठबंधन तय भी कर लिया है। कहा जाता है कि वोटर को मजबूत नेता चाहिए। इस पैमाने पर भी योगी और अखिलेश खरे उत्तरते हैं। योगी को संघ परिवार का सहारा है तो अखिलेश को मुलायम सिंह परिवार में एकजुटता होने से बड़ा सहारा मिला है। कहा जा रहा है कि जाति के आधार पर चुनाव लड़ा गया तो अखिलेश कड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं लेकिन अगर धर्म हावी रहा यानि हिन्दूत्व ने जाति को 2014 और 2017 की तरह तोड़ तो फिर योगी की चांदी हो सकती है।

योगी कभी कारसेवकों पर गोली चलाए जाने की घटना को याद करते हैं और इस बहाने 'मौलाना मुलायम' के काल को सामने रखते हैं तो कभी कैरना जाकर वहां से हुए कथित पलायन की याद करते हैं। साथ ही साथ सीधे चेतावनी देते हैं कि भविष्य में कैरना दोहराया नहीं जाएगा।

हालांकि इस हिन्दूवाद का दूसरा पहलू यह है कि योगी आदित्यनाथ 18 से 20 प्रतिशत वोटरों को ही प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। यानि ऐसे वोटर जो उग्र हिन्दूत्व विचारधारा के प्रवाह में बह सकते हैं इसके साथ ही गोरखनाथ मठ के अनुयायी हैं जो स्वाभाविक रूप से योगी आदित्यनाथ के परम भक्त हैं और वोट उसी ओर जाना है।

ऐसा लगता है कि भाजपा को अभी भी उम्मीद है कि सांप्रदायिक ध्वनीकरण का कार्ड चल सकता है हिन्दूत्व का झंडा अगर योगी ने थामा है तो विकास का ध्वज फहराने का जिम्मा उठा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, जो विकास के नाम पर 50 प्रतिशत वोटरों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। गैस सिलेंडर की उज्ज्वला योजना की शुरुआत यूपी के बलिया से की गई थी और पार्टी-2 की शुरुआत भी यूपी के महोबा से की गई। मुफ्त पांच किलो अनाज के साथ एक किलो दाल, एक किलो तेल, एक किलो चीनी भी दी जाएगी। जोर शोर से प्रचारित किया जा रहा है कि यूपी में 15 करोड़ लोगों को इससे फायदा होगा। इसी तरह उजला, इज्जत घर के

बाद हर घर नल के लिए जल योजना को भी गेम चेंजर बताया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 19 फीसदी मुस्लिम वोटों पर तो एकतरफा अखिलेश यादव के बीच होने जा रहा है। दोनों यानि भाजपा और समाजवादी पार्टी ने अपने-अपने सहयोगी दल चिह्नित भी कर लिए हैं और गठबंधन तय भी कर लिया है। कहा जाता है कि वोटर को मजबूत नेता चाहिए। इस पैमाने पर भी योगी और अखिलेश खरे उत्तरते हैं। योगी को संघ परिवार का सहारा है तो अखिलेश को मुलायम सिंह परिवार में एकजुटता होने से बड़ा सहारा मिला है। कहा जा रहा है कि जाति के आधार पर चुनाव लड़ा गया तो अखिलेश कड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं लेकिन अगर धर्म हावी रहा यानि हिन्दूत्व ने जाति को 2014 और 2017 की तरह तोड़ तो फिर योगी की चांदी हो सकती है।

पिता के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते। हाल ही में जिना को महात्मा गांधी और सरदार पटेल के साथ आजादी दिलाने वालों में शामिल करने वाले बयान पर बवाल मचा था।

दरअसल योगी के लिए हिन्दूत्व की बात करना सियासी मजबूरी है क्योंकि वह नहीं चाहते कि यूपी में चुनाव जाति के आधार पर लड़ा जाए। अब जाति को धर्म ही तोड़ता है लिहाजा वह रामभरोसे हो रहे हैं।

योगी चाहते हैं कि चुनाव सीधे-सीधे मुस्लिम-यादव एक तरफ, बाकी सारे एक ओर हो जाए। उधर मोदी विकास के नाम पर लाभार्थियों का ध्वनीकरण करें। इसके बावजूद भाजपा कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। लिहाजा उसने अपना दल से लेकर निषाद पार्टी तक से चुनावी समझौता किया है।

उधर अखिलेश को उम्मीद है कि यादव वोट बैंक के साथ साथ पूरा मुस्लिम वोट उनके पास आएगा तक से चुनावी समझौता किया है।

साथ ही ओम प्रकाश राजभर की सुलेहदेव भारतीय समाज पार्टी, महान दल, जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल और चन्द्रशेखर रावण की दिलित सेना साइकिल को धक्का लगाएंगी तो साइकिल सत्ता की सड़क पर सरपट दौड़ेंगी।

जानकारों का कहना है कि अगर यूपी में 04 बड़े दल यानि भाजपा, सपा, और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो 30-31 प्रतिशत वोट सत्ता दिलाने के लिए बहुत होंगे। अब आंकड़ों को समझते हैं। भाजपा को 2017 के विधान सभा चुनाव में करीब 40 फीसद वोट मिले थे।

अगर हम इस ट्रैड को देखें तो भाजपा का 7-8 फीसदी वोट फिर से होने वाले चुनाव में औसत रूप से कम हो जाता है तो भी उसके पास करीब 32 प्रतिशत वोट होंगे। यानि जीत 325 की न होकर हो सकता है कि 225-250 के बीच की हो। लेकिन भाजपा का अगर 7-8 प्रतिशत वोट कम हुआ तो वो किसी एक दल के पास यानि अखिलेश के पास पूरी तरह से आ जाएगा, यह तय नहीं है, यानि किसी एक विपक्षी दल के काम नहीं आएगा।

चौथा, जो लोग ममता बनर्जी अथवा केजरीवाल या यहां तक कि शरद पवार की तरह विस्तार के मद्देनजर वहां जा रहे हैं वे सभी प्रधानमंत्री बनने की आकांक्षाएं पाले हुए हैं। अंततः अन्य पार्टियां एक अवसर देख रही हैं, जबकि कांग्रेस तथा भाजपा दो मुख्य पार्टियां हैं और तीसरी पार्टी के पास एक विकल्प के तौर पर उभरने का अवसर है। चुनाव काफी भीषण होंगे जिसमें पर्यावरण से लेकर खनन तथा कोविड से निपटने के मामले शामिल होंगे।

बाकी पेज 11 पर

## गोवा- चुनावी युद्ध के लिए पार्टियों ने कसी कमर

छोटे राज्य गोवा में विधानसभा चुनावों के लिए युद्ध रेखाएं खिंच गई हैं जिसमें अगले वर्ष के शुरू में चुनाव होने हैं। चुनावी परिदृश्य भीड़भाड़ वाला होने की संभावना है जिसमें कम से कम 8 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। सत्ताधारी भाजपा तथा विपक्षी कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस व आम आदमी पार्टी जैसे कुछ बाहरी प्रतिस्पद्धी मैदान में हैं। इस बहुकोणीय स्पर्धा का परिणाम संभवतः खंडित होगा क्योंकि कोई भी पार्टी बहुमत हासिल करने की स्थिति में नहीं होगी।

क्यों तृणमूल कांग्रेस तथा 'आप' जैसे क्षेत्रीय दलों की नज़र गोवा पर है? पहला, राकांपा, 'आप' तथा तृणमूल सहित सभी पार्टियों की राष्ट्रीय समर्पण करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही अधिकतर गोवावासियों के लिए

पर एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में पहनाने जाने के लिए किसी पार्टी का चार राज्यों से लोकसभा में कम से कम 2 प्रतिशत प्रतिनिधित्व हो, कम से कम चार राज्यों में विधानसभा तथा लोकसभा में 6 प्रतिशत वोटें पड़ी हों तथा किसी भी राज्य में कम से कम चार संसद हों।

दूसरा, यद्यपि गोवा सबसे छोटा राज्य है जिसकी मात्र 02 लोकसभा सीटें तथा 40 सदस्यीय विधानसभा है, यह संसद में किसी भी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण संख्या नहीं जोड़ सकता लेकिन मत हिस्सेदारी मायने रखती है।

तीसरा, गोवा के छोटे से निर्वाचन क्षेत्रों को चुनाव के लिए बहुत अधिक दोहरी वोटों की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही अधिकतर गोवावासियों के लिए

### कल्याणी शंकर

भाषा कोई अवरोध नहीं है जो अंग्रेजी बोलते हैं।

चौथा, जो लोग ममता बनर्जी अथवा केजरीवाल या यहां तक कि शरद पवार की तरह विस्तार के मद्देनजर वहां जा रहे हैं वे सभी प्रधानमंत्री बनने की आकांक्षाएं पाले हुए हैं। अंततः अन्य पार्टियां एक अवसर देख रही हैं, जबकि कांग्रेस तथा भाजपा दो मुख्य पार्टियां हैं और तीसरी पार्टी के पास एक विकल्प के तौर पर उभरने का अवसर है। चुनाव काफी भीषण होंगे जिसमें पर्यावरण से लेकर खनन तथा कोविड से निपटने के मामले शामिल होंगे।

## अखिलेश रालोद को 36 सीटें देने पर सहमत

आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में यह एक कटु सत्य बनकर उभरा है कि सत्तारुद्ध भाजपा को अगर हराना है तो गठबंधन करना हर दल की मजबूरी बन चुकी है। ऐसा ही एक गठबंधन पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में रालोद और समाजवादी पार्टी में हुआ है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी (सपा) और राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) ने सीटों के बंटवारे को लगभग अन्तिम रूप दे दिया। सूत्रों के अनुसार लखनऊ में रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ बैठक में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रालोद को 36 सीटें देने पर सहमति जताई है। हालांकि इसमें से छह सीटों पर उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के होंगे लेकिन वह रालोद के चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसा ही नज़ारा कैरना में 2018 के लोकसभा उपचुनाव में देखने को मिला था, जब समाजवादी पार्टी की तबस्सुम हसन ने रालोद के टिकट पर चुनाव लड़ा था। सपा के एक नेता ने बताया, यह रणनीति चुनाव में अच्छी तरह से काम करेगी क्योंकि दोनों दलों के कार्यकर्ता उम्मीदवारों के साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का दावा है कि रालोद पश्चिमी यूपी में पहले से काफी बेहतर स्थिति में है, विशेषकर किसान आंदोलन के बाद जिसमें जयंत चौधरी ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। बिना किसी सहयोगी के हुई इस समझौते बैठक में दोनों नेताओं ने कृषि कानूनों को निरस्त करने के केन्द्र फैसले के बाद राज्य के परिवर्ती हिस्से में राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की। एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम के बारे में भी बातचीत हुई, हालांकि रालोद ने पिछले दिनों अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। यह निर्णय लिया गया है कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने वाली पार्टियां विधानसभा चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। इससे एक बाद इस सियासी हलचल में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आम आदमी पार्टी (आप) के नेता से मुलाकात की। आम आदमी पार्टी सासद संजय सिंह ने लोहिया ट्रस्ट कार्यालय में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अपनी चर्चा के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन अपुष्ट सूत्रों के अनुसार आम आदमी पार्टी सासद ने अखिलेश यादव को 25 सीटों की सूची सौंपी है। आप ने पहले ही घोषणा की थी कि वह सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी।

# उपलब्धियाँ तभान लैकिन रहेगा मलाल

संयुक्त अरब अमीरात में हुए टी-20 वर्ल्ड कप में भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही, उसे शुरुआत में ही में अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद भी टीम की कोई विशेष उपलब्धि नहीं रही। इस सीरीज के साथ ही टीम इंडिया के मुख्य कोच रवि शास्त्री का कार्यकाल पर भी विराम लग गया। और अब टीम की कमान राहुल द्रविड़ के हाथों में है जिन्होंने पहली ही सीरीज में शानदार शुरुआत करते हुए टीम इंडिया को 3-0 से शिकस्त दी।

रवि शास्त्री ने विराट एंड कंपनी के साथ 2017 में अपनी पारी शुरू की थी। इस दौरान उन्होंने तमाम उपलब्धियाँ हासिल कीं। लेकिन रवि शास्त्री को एक कोच के तौर पर कोई भी आइसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पाने का मलाल हमेशा रहेगा। यह सही है कि किसी भी टीम के लिए आस्ट्रेलिया से उसके घर में टेस्ट सीरीज जीतना किसी भी आइसीसी ट्रॉफी जीतने से कम नहीं है और यह कारनामा उनके कार्यकाल में ही टीम इंडिया ने दो बार दोहराया।

रवि शास्त्री को टीम इंडिया के चार वर्ष तक कोच रहने के दौरान तीन बार आइसीसी ट्रॉफी जीतने का मौका मिला पर हर बार उन्हें नाकामी

ही मिली। शास्त्री के कोच बनने के बाद 2019 के आइसीसी विश्व कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हार गया। इस वर्ष पहली विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड से हार गया। बीते टी-20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया सेमीफाइनल तक में जगह बनाने में विफल रही। हम सभी

जानते हैं कि आइसीसी ट्रॉफियों को जीतना एक अलग ही बात होती है। यही वजह है कि भारत के सफलतम कप्तानों की जब भी बात चलती है तो सबसे पहले कपिल देव और महेन्द्र सिंह धोनी का ही नाम आता है।

शास्त्री ने मौजूदा टी-20 विश्व

कप में सुपर 12 का अपना आखिरी मैच नामीबिया से खेलने से पहले कहा था कि मैं मेरा स्थान लेने वाले कोच राहुल द्रविड़ को टीम को नई ऊंचाईयों पर पहुंचाने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। अच्छी बात यह है कि द्रविड़ को बदलाव के गुजरने वाली टीम नहीं है। यह टीम पहले से ही महान है। इस टीम के ज्यादा

खिलाड़ी अभी तीन चार साल खेल सकते हैं। मुझे भरोसा है कि द्रविड़ का अनुभव टीम को और आगे ले जाएगा। एक अच्छी बात यह है कि द्रविड़ टीम इंडिया के खिलाड़ियों के साथ पहले से जुड़े रहे हैं, इसलिए उन्हें काम करने में शायद ही कोई दिक्कत हो।

हम सभी जानते हैं कि 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत के पाकिस्तान से हारने के बाद कप्तान विराट कोहली के तत्कालीन कोच अनिल कुंबले से मतभेद सामने आने के बाद ही अनिल कुंबले की जगह रवि शास्त्री का मुख्य कोच के पद से नियुक्त की गई थी। उनकी पहली बड़ी परीक्षा 2019 के विश्व कप में हुई। भारत जिस अंदाज में गुप्त के सभी मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचा, उससे लग रहा था कि इस बार उनका चैम्पियन बनने का सपना ज़रूर साकार हो जाएगा। लेकिन न्यूजीलैंड ने एक बार फिर एकजुट प्रदर्शन से भारत को मात देकर आइसीसी मुकाबलों में अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखा। इसके बाद विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में हारने के बाद शास्त्री की विदाई तय हो गई थी। इसकी वजह बीसीसीआई ऐसा कोच चाहता था कि जो आइसीसी ट्रॉफी को जिता सके।

## आस्ट्रेलिया 24 वर्ष के बाद पाकिस्तान दौरे को तैयार

सुरक्षा कारणों से हाल ही में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के द्वारा पाकिस्तान दौरा रद्द करने के बाद आस्ट्रेलिया ने 24 वर्ष के बाद पाकिस्तान में पूर्ण श्रृंखला (सीमित ओवरों के साथ टेस्ट श्रृंखला) खेलने पर हामी भर दी है। आस्ट्रेलिया ने पिछली बार 1998 में पाकिस्तान का दौरा किया था। वह अगले वर्ष मार्च में शुरू होने वाले दौरे पर तीन टेस्ट मैच खेलेगा। विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के तहत खेले जाने वाले इन मैचों का आयोजन कराची (तीन से सात मार्च), रावलपिंडी (12 से 16 मार्च), और लाहौर (21 से 25 मार्च) में किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में इस दौरे की जानकारी देते हुए कहा कि सीमित ओवरों के चार मैच 29 मार्च से 05 अप्रैल के बीच खेले जायेंगे। इस वर्ष सितंबर में न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान पहुंचने के बाद सुरक्षा कारणों के कारण एक भी मैच खेले बिना ही घर वापस लौट गयी थी। इसके तुरंत बाद, इंग्लैंड ने भी घोषणा की कि वे टी-20 विश्व कप से पहले इस देश का दौरा नहीं करेंगे। आस्ट्रेलिया का पाकिस्तान में आना हाल में पीसीबी के प्रमुख बने रमेज़ राजा के लिए एक बड़ी जीत है, जिन्हें इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के हटने के बाद आस्ट्रेलियाई टीम के दौरे की उम्मीद नहीं थी। राजा ने एक बयान में कहा “मुझे खुशी है कि हम तीन टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेलेंगे। बहुत बड़ी खुशी है।” उन्होंने कहा कि आस्ट्रेलिया शानदार प्रदर्शन करने वाली टीमों में से एक है और 24 वर्ष के अंतराल के बाद पहली बार हमारे देश में खेलना प्रशंसकों के लिए एक विशेष पल होगा। क्रिकेट आस्ट्रेलिया के मुख्य कार्यकारी निक हॉकल ने कहा कि वे अपनी टीम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पीसीबी के साथ काम करना जारी रखेंगे।

## स्वास्थ्य

# सदियों का कर्देंवेलकम

सर्दियों ने दरवाजे पर दस्तक दे दी हैं आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखने में जुटे हैं। ऐसे में अपने प्यारे घर का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। आप इस मौसम का आनंद तभी उठा पाएंगे अगर आपने आसपास के परिवेश को सर्दी के अनुकूल ढालने का प्रयास किया होगा। ठण्डे से बचने के लिए ज़रूरी है कि घर का वातावरण को जी होने के साथ-साथ हवादार व तरोताज़ा भी हो। आईए जानें कुछ खास बातें :-

संगों का मौसम :- कोई कुछ भी कहे, सच तो यह है कि सर्दी का मौसम रंगों का मौसम है। गर्मी में चुभने वाले गहरे रंग सर्दी में मन को भाने लगते हैं। इसलिए जितना हो सके, गुहरे रंगों से घर को सजाएं। गहरा लाल, नीला, हरा, गुलाबी हरा रंग खिला खिला महसूस करवाएंगा।

आपके आशियाने को। गोल्ड बेज, ओरेंज, रेड, रस्टिक रंग घर को वार्म महसूस करवाते हैं। आप बार-बार दीवारों के रंग नहीं बदल सकते। ऐसे में इन रंगों के वॉल पेपर इस्टेमाल करें। कलर कार्ड लें और अपनी पसंद के रंग चुनें।

### गर्म नरम कुशन कवर

सर्दियों में हर किसी को नरम, आरामदायक व गर्म कपड़ों का ही इस्टेमाल करना अच्छा लगता है, फिर चाहे वह खुद पहनने वाले कपड़े हों या कमरे में इस्टेमाल होने वाला सामान। आप कमरे में सजावट के लिए गर्म कपड़े या मखमली कपड़े और फर इस्टेमाल कर सकते हैं। कशमीरी कपड़ा भी एक अच्छा विकल्प है, जिसे आप सोफे या बेडकवर के रूप में इस्टेमाल कर सकते हैं। सोफे पर ज़्यादा माहौल पैदा कर सकते हैं।

मौसम के अनुसार इंटीरियर बदलकर आप अपने आशियाने में चार चांद लगा सकते हैं।

### फर्श के लिए कार्पेट

पैरों को गर्म रखने के लिए घर में कार्पेट बिछाएं। आजकल बाजार

में कई रंग, डिजाइन, पैटर्न, साइज व आकार के कार्पेट उपलब्ध हैं। ध्यान रहे कि आप जो भी कार्पेट खरीदें, वह आपके घर की मौजूदा शैली और रंग के अनुसार ही हो। घर के सोफे, बेड, डायनिंग टेबल के सामने भी कार्पेट बिछाने से आपके पैर हर समय गर्म रहेंगे। चटकीले रंग के कालीन से आपके कमरे में जान आ जाएंगी।

### बेडरूम में परतें बिछाएं

बेडरूम को गर्म रखने के लिए अपने बिस्तर पर रखाई या कंबल कई परतों में बिछाएं। इससे न केवल

आपका बिस्तर गर्म होगा बल्कि नरम और आरामदायक भी बन जाएगा। यदि आप बेडरूम का रूप बदलना चाहते हैं तो कमरे में कुछ और लाइटें लगाएं। ठण्डी हवा से बचाव बाहर की ठंडी हवा से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप खिड़की व दरवाज़ों को चेक करें कि वहां से ठण्डी हवाएं आपके घर में न आएं। घर में ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी और रोशनी की कमी से बचने के लिए खूबसूरत पर्दे लगाएं। इससे ठण्डे से बचने के अलावा बिजली के बिल में भी कमी होगी। दिखने-सुनने में सामान्य ये टिप्प अगर हम अपनायें तो घर के वातावरण को सही बनाये रखकर हम अपने और अपने बच्चे के स्वास्थ्य को सही रखने में कामयाब हो सकते हैं।

## शेष.... चीन में मुसलमानों की....

और यहूदियों को 'गुलामों' की तरह माना गया। उन पर तरह-तरह के टैक्स ठोक दिए गए।

ज्यों-ज्यों मध्य एशिया और अरब के साथ चीन का व्यापार और आवागमन बढ़ता गया, चीन में मुसलमानों की संख्या भी बढ़ती गई। उनकी संपत्ति और शक्ति भी काफी बढ़ने लगी। 'हुई मुसलमानों' के मुक़ाबले मध्य एशिया के मुसलमानों का दबदबा ज्यों ही बढ़ने लगा, चीनी सम्राटों ने बड़ी बेरहमी से उन्हें मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। 'हुई मुसलमान' तो किसी तरह चीन में खपते रहे लेकिन शिन च्यांग के उड़गर मुसलमानों ने बग़वत का तेवर इख़्तयार कर लिया।

चीन के उड़गर मुसलमान मुख्यतः शिन च्यांग नामक प्रांत में रहते हैं। इसे सिंक्यांग भी कहते हैं। यह चीन के उत्तर और पश्चिम में हैं। इसकी सीमाएं लदाख और कश्मीर को छूती हैं। सैकड़ों वर्ष पहले भारत के जैन और बौद्ध संत इसी प्रांत से होकर चीन में दूर-दूर तक पहुंचते थे। शिन-च्यांग प्रांत की संख्या लगभग सवा दो करोड़ है, जिसमें सवा करोड़ उड़गर हैं, जो वहाँ के मूल निवासी हैं लेकिन पिछले 60-70 साल में चीनी सरकार ने लगभग एक करोड़ हान चीनियों को वहाँ बसा दिया है। बीसवीं सदी में उड़गरों का जब मध्य एशिया के राष्ट्रों और अफ़ग़ानिस्तान, तुर्की,

इरान आदि राष्ट्रों से संपर्क बढ़ा तो उन्होंने स्वतंत्र तुर्किस्तान की मांग पर आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन को दबाने के लिए पहले चरण में च्यांग काई शेक और माओ त्से तुंग की कम्युनिस्ट सरकार ने शिन च्यांग में खून की नदियां बहा दी थीं।

अत्याचारों का वही सिलसिला अब भी जारी है। पिछले 25-30 साल में मेरा चीन जाना कई बार हुआ है। चीनी सरकार ने मुझे तिब्बत कभी नहीं जाने दिया लेकिन मुझे चीन के इस मुस्लिम प्रांत में अनुवादक के ज़रिए बात करने का और कई स्थानों पर जाने का अवसर भी मिला। कुछ उड़गर नेताओं और प्रोप्रेसों से फारसी में खुलकर सीधे बात करके मुझे अनेक विशिष्ट जानकारियां भी मिलीं। मुझे कई उड़गरों ने कहा कि वे यहाँ गुलामी की ज़िन्दगी जी रहे हैं। उन्हें मस्जिदों में जाने से रोका जाता है। उन्हें दाढ़ी नहीं रखने दी जाती है। सारा सरकारी काम काज चीनी भाषा में ही होता है हमारी अपनी तुर्की भाषा की सरकार में पूरी तरह उपेक्षा होती है। हमारे इमामों और मौलानाओं को चीनी पुलिसवाले जब चाहे थानों में बंद कर देते हैं। हमारे बच्चों पर स्कूलों में चीनी भाषा थोप दी जाती है। हमारे सारे बड़े अधिकारी हान जाति के हैं। सरकार की कोशिश है कि अपने ही 'मुल्क' में हम अल्पसंख्यक बन जाएं। □□

## शेष.... गोवा- चनावी घट्ट के लिए....

भाजपा, कांग्रेस, तृणमूल तथा 'आप' से शीर्ष नेता पहले ही हाई प्रोफाइल प्रचार अभियान शुरू कर चुके हैं। गोवा फार्वर्ड पार्टी (जी.एफ.पी.) तथा महाराष्ट्रवादी गोमातक पार्टी (एम.जी.पी.) ने भी प्रयास शुरू कर दिए हैं। भाजपा प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम पर बोट मांगे। अब तक किसी भी पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है।

जहाँ तक कांग्रेस की बात है, गत माह तृणमूल कांग्रेस की गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री लुईजिन्हो फ्लेरो को खोना एक बहुत बड़ी चोट थी। पार्टी अब 17 विधायिकों से 4 विधायिकों तक सिमट गई है। इनमें से 3 गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सभी चले हुए कारतूस। तृणमूल कांग्रेस की गोवा में विस्तार की बड़ी महत्वकांक्षाएं हैं जिसके लिए पश्चिम बंगाल की गोवा के मुख्यमंत्री राजनीतिक आकांक्षाएं हैं।

'आम आदमी पार्टी' की भी उल्लेखनीय राजनीतिक आकांक्षाएं हैं। यह कई तरह के प्रलोभन पेश कर रही है जैसे कि एक माह में 300 यूनिट बिजली मुफ्त, निजी नौकरियों में स्थानीय लोगों को 80 प्रतिशत आरक्षण तथा पर्यटन व खनन क्षेत्रों के लिए रोज़गार भत्ता।

अरविंद केजरीवाल एम.जी.पी. के विधायक राम कृष्णन उर्फ सुर्दिन ध वालिकर को अपने खेमे में लाने का प्रयास कर रहे हैं। एम.जी.पी. किसी समय गोवा की सत्ताधारी पार्टी थी तथा भाजपा ने इसके समर्थन से गोवा की राजनीति में प्रवेश किया था। मगर भाजपा द्वारा एम.जी.पी. में सेंध लगाने के बाद पार्टी ने भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ दिया था।

आने वाले विधानसभा चुनाव सत्ता विरोधी लहर के कारण भाजपा के लिए आसान नहीं होंगे। विपक्ष में विखंडन संभवतः भाजपा के लिए चीजें आसान कर देगा। ब्रह्माचार तथा सत्ता विरोधी लहर 02 महत्वपूर्ण कारक हैं।

'आप' का मुक़ाबला करते हुए भाजपा ने भी प्रत्येक घर को मुफ्त पानी का वायदा किया है। इसने 10,000 नई सरकारी नौकरियों का भी वायदा किया है और 'सरकार तुमच्या दारी' अर्थात् सरकार ने 'आप' के द्वारा पर' नामक एक आऊटरीच

इधर कुछ विश्व संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने काफी खोज बीन करके जो रपटें बनाई हैं, वे शिन च्यांग के ताजा हालात को काफी चिंताजनक बता रही है। वहाँ लगभग 1600 छोटी बड़ी मजिस्ट्रें तोड़ दी गई हैं। कुरआन की प्रतियों को खुलेआम जलाया जाता है, मुहर्रम के जुलूसों पर प्रतिबंध है, अज़ान की आवाज़ मस्जिद के बाहर नहीं जा सकती और मुस्लिम औरतों का ज़बरदस्ती बंध्याकरण कर दिया जाता है। चीन के बड़े शहरों में जहाँ भी मुसलमानों की बसियां और दुकानें हैं, उन पर जासूसों की कड़ी निगरानी रहती है। मुझे अमेरिका में मिले कई हान और उड़गर चीनियों ने बताया कि उनके कई रिशेदारों के शरीर से कुछ अंगों को ज़बरदस्ती निकाल लिया जाता रहा है। इसके अलावा जिस तथ्य को लेकर सारे संसार में चीन की निंदा हो रही है, वह है शिन च्यांग के यातना शिविर, जिनमें 10 से 15 लाख उड़गर मुसलमानों को कैद करके रखा गया है और इन्हें इस्लाम विरोधी शिक्षा दी जाती है। उनसे कठोर शारीरिक श्रम भी करवाया जाता है। चीनी सरकार का कहना है कि ये हिटलर के यंत्रणा शिविरों की तरह नहीं हैं। ये शिक्षा शिविर हैं, जहाँ उड़गर मुसलमानों को चीनी सभ्यता संस्कृति और देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाता है। □□

## कांग्रेस ने कोरोना मृतकों के परिवारों के लिए छेड़ा अभियान

कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार से देश में कोरोना वायरस से मरने वालों के परिवारों को 4 लाख रुपये का मुआवजा देने की अपील की है। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले कांग्रेस ने कोविड महामारी में मृतक परिवारों को 4 लाख का मुआवजा देने के कैम्पनी की शुरूआत की है। इसके साथ ही कांग्रेस ने कोविड महामारी के गठन की मांग की है। कांग्रेस प्रवक्ता गैरव वल्लभ ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चार लाख मुआवजा कैम्पन चलाया है और मांग की है कि सरकार को कोविड पीड़ितों का वास्तविक अंकड़ा बताना चाहिए। उन परिवारों को 4 लाख रुपये का मुआवजा देना चाहिए, जिनके सदस्यों की कोविड से मौत हुम्हरे है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि राज्य सरकारें अपने हिस्से की रकम देने के लिये तैयार हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि कोरोना मृतकों को 4 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। शीतकालीन सत्र से पहले इन परिवारों को केंद्र सरकार की ओर से राहत दी जाए। गैरव वल्लभ ने कहा कि देश में दूसरी लहर 11 महीने बाद आई। जब दुनिया के सारे देश अपने नागरिकों का वैक्सीनेशन कर रहे थे। तब हम ताली-थाली बजा रहे थे और देश की वैक्सीन हम निर्यात कर रहे थे। मोदी जी आपकी तपस्या में कमी नहीं है, समस्या समझने में कमी हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 4 अक्टूबर के फैसले में, कोविड पीड़ितों के परिजनों के लिए 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि को मंजूरी दी थी, जिसकी सिफारिश राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने की थी।

## मोदी से मिली ममता : त्रिपुरा हिंसा और बीएसएफ क्षेत्र का मुद्दा उठाया

तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमों और पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पिछले दिनों दिल्ली में थी। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाक़ात की। मोदी से मुलाकात के बाद मोदी को बातचीत करते हुए ममता बनर्जी ने कहा - 'मैंने राज्य से जुड़े कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी से बातचीत की है। हमने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के विस्तार के मुद्दे पर भी बात की ओर इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। प्रधानमंत्री से मुलाकात में ममता ने राज्य के विकास के विभिन्न मुद्दों के अलावा त्रिपुरा में हिंसा के मामले पर चर्चा की। ममता ने आरोप लगाया है कि त्रिपुरा में बिप्लब देव की सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन कर रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में टीएमसी की प्रचंड जीत के बाद ममता की दिल्ली की यह दूसरी यात्रा थी।

## शेष.... आज फिर नेहरु और....

सालों में महत्वपूर्ण यह था कि कौन सी चीजें उन्हें जोड़े रखती हैं। नेहरु और पटेल दोनों में ही अपने देश के प्रति गहरा प्रेम था, देश की एकता को लेकर प्रतिबद्धता थी और उनमें यह समझ थी कि उन पर उनके साझा गुरु महात्मा गांधी की स्मृतियों का कर्ज़ है, जिसके लिए उन्हें आपस में मिलकर काम करना और कठोर मेहनत करनी है। आयंगर लिखते हैं, दोनों अनथक कार्यकर्ता थे, खुद को न तो शारीरिक और न ही मानसिक आराम के लिए समय देते थे। आयंगर की तरह मैं भी क्रिकेट का फैन हूं। 1970 के दशक में मुझे तब बहुत कांग्रेस की बाजी और तेंदुलकर में से किसी एक को चुनूं। नेहरु और पटेल की सांझेदारी क्रिकेट के मैदान में बनी किसी भी जोड़ी से असीमित रूप से महान थी। उनमें से किसी एक को ऊंचा दिखाने और दूसरे को नीचा दिखाने से हमें उन दोनों की स्मृतियों का ही अपमान करेंगे और इससे भारत की भी अवमानना होगी। □□

## शेष.... मंज़र पस-मंज़र

सहयोग का कैसा ढांचा खड़ा किया है? विडंबना यह है कि सतह पर दिखती चकाचौंध आमतौर पर ज़मीनी हकीकत से काफी दूर होती है, मगर अक्सर उसी को प्रतिनिधि छवि मान लिया जाता है। दरअसल, कुछ छवियों के आधार पर सामाजिक सहयोग को भले ही एक सकारात्मक चलन के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन सच यह है कि वक्त के साथ सामाजिक सहयोग और संवेदना के मामले में भी तेज़ी से छीजन आई हैं आपसी व्यवहार और जुड़ाव के मामले में बनते दायरे के समातंर यह भी कड़ी हकीकत है कि सरकारी स्तर पर घोषित ग्रीष्मी उन्मूलन कार्यक्रमों और योजनाओं की पहुंच वास्तविक ज़रूरतदातों तक यात्रा हो गई है। अगर ऐसा आमतौर पर होने लगता है तब इस तरह की योजनाओं के कोई मायने नहीं रह जाते। आज हालत यह है कि भुखम

# आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ें ममत्व बनाम बेबसी

## आत्मनिर्भरता की ओर

वाणिज्य मंत्रालय ने कुछ ऐसी वस्तुओं को चिह्नित किया है, जिनका उत्पादन अपने देश में बढ़ाया जा सकता है इसलिए उन्हें बाहरी देशों से मंगाने की प्रक्रिया धीरे-धीरे कम करनी चाहिए। इस संबंध में वाणिज्य मंत्रालय ने एक सौ दो वस्तुओं की सूचि जारी करते हुए संबंधित मंत्रालयों को इनके आयात में कटौती करने को कहा है। गैरतरलब है कि इन एक सौ दो वस्तुओं की देश के कुल आयात में भागीदारी सत्तानवें प्रतिशत से अधिक है। इनमें से 18 वस्तुएं ऐसी हैं, जिनका आयात लगातार बढ़ रहा है, जबकि अपने देश में उनके उत्पादन की भरपूर संभावनाएं हैं। जिन वस्तुओं के आयात में कटौती की सलाह दी गई है, वे मुख्य रूप से कोकिंग कोयला, कुछ मशीनरी उपकरण, रसायन और डिजिटल कैमरा शामिल हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं, जिनका अपने देश में भी उत्पादन भरपूर होता है, मगर आयतित माल की वजह से उन्हें घरेलू बाजार में उचित भागीदारी नहीं मिल पाती। उनमें निजी कंप्यूटर, पाम आूयल, सूरजमुखी का तेल, यूरिया, फास्फोरिक एसिड आदि प्रमुख हैं। सरकार वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनने का नारा दे चुकी है। इस दिशा में पहले ही बाहर से मंगाई जाने वाली कई वस्तुओं में कटौती की जा चुकी है। ताज़ा फैसला उससे आगे की कड़ी है।

काफी समय से इस बात को लेकर चिंता जताई जाती रही है कि देश में आयात तो ढ़ रही है, पर निर्यात लगातार घट रहा है। आयात

## ज़रूरी ऐलान

आपकी खरीदारी अवधि पते की चिट पर अंकित है। अवधि की समाप्ति से पूर्व रकम भेजने की कृपा करें।

## रकम भेजने के तरीके

① मनीआर्ड द्वारा ② Paytm या PhonePe द्वारा 9811198820 पर SHANTI MISSION  
③ ऑनलाइन हेतु बैंक खाते का विवरण SBI A/c 10310541455 Branch: Indraprastha Estate IFS Code: SBIN0001187

उन्हें बाहर के बाजार में जगह नहीं मिल पाती, दूसरे घरेलू बाजार में भी विदेशी वस्तुओं का बोलबाला बढ़ जाता है। मगर कुछ मामलों में भारत की आयत पर निर्भरता इस क़दर बढ़ गई है कि सरकारों के लिए खुद बाहर से वस्तुएं मंगाना ज्यादा आसान लगता है। इस तरह विदेशी कंपनियों ने भारतीय घरेलू बाजार में घुसपैठ कर सस्ती दरों पर उच्च गुणवत्ता की वस्तुएं उपलब्ध कराने के दावे के साथ अपनी साख मज़बूत बना ली है। कई कंपनियों ने तो एक तरह से अपना एकाधिकार जमा लिया है। इस एकाधिकार को तोड़े बगैर देशी वस्तुओं के उत्पादन और खपत की गुंजाइश पैदा कर पाना कठिन ही बना रहेगा। इस मामले में वाणिज्य मंत्रालय का यह फैसला उचित है कि उसने आयात के मामले में अधिक जगह घरेने वाली कुछ वस्तुओं को चिह्नित कर उनकी जगह देशी वस्तुओं की पहुंच सुनिश्चित करने की पहल की है।

भारत अब दुनिया के विकसित देशों से कारोबारी होड़ कर रहा है। सॉफ्टवेयर और सूचना तकनीक आदि

कई क्षेत्रों में यह दूसरे देशों की बड़ी ज़रूरतें भी पूरी करता है। बहुत सारी विदेशी कंपनियां सेवाओं के मामले में भारत पर निर्भर हैं। फिर भी विदेशी बाजार में भारतीय कंपनियां अपने लिए बड़ी जगह नहीं तलाश पा रहीं, जबकि चीन जैसे देश छोटी-छोटी चीजों के मामले में भी हमारे घरेलू बाजार में कड़ी प्रतिस्पध दे रहे हैं। इस तरह आयात में कमी लाने से घरेलू वस्तुओं के लिए बाजार में जगह बढ़ेगी। मगर इसके लिए सरकार को उन बिंदुओं पर भी सतत ध्यान देना होगा, जिसके चलते कई मामलों में घरेलू कंपनियों ने उत्पादन बंद ही कर दिया। नहीं तो केवल आयात कम करने का सैद्धांतिक फैसला खेती किसानी, खाद्य तेल, बिजली उत्पादन जैसे क्षेत्रों में बड़े संकट पैदा कर सकता है।

**ममत्व बनाम बेबसी**  
जिस दौर में अर्थव्यवस्था के ऊंची उड़ान भरने के दावे किए जा रहे हैं, उसी में चमकती तस्वीर के बरक्स अलग-अलग पैमाने पर गरीबी की त्रासद छवियां भी सामने आ

रहीं हैं, तो उसे किस तरह देखा जाएंगा? महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के शिरडी शहर में जिन परिस्थितियों में एक महिला ने अपने तीन दिन के नवजात को बेच दिया, उससे एक बार फिर यह प्रश्न पैदा होता है कि आखिर किसी देश में विकास की परिभाषा क्या है। ख़बर के मुताबिक एक महिला ने बीते सितंबर में एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन उसकी आय या आर्थिक स्थिति इस हद तक ख़राब रही कि वह खुद सहित बच्चे के पालन पोषण में असमर्थ थी। शायद उसे अपने आने वाले दिनों में भी आय और अपना खर्च चला पाने के बारे में हालात का अंदाज़ा था, इसलिए कोई विकल्प न पाकर कुछ धन की उम्मीद में उसने अपने बच्चे का ही सौदा करने का फैसला कर लिया। अहमदनगर और ठाणे की तीन महिलाओं की मदद से उसने एक व्यक्ति को एक लाख 78 हजार रुपए में बच्चा बेच दिया। एक घटना जो प्रकाश में आ गई तो अखबारों में छप गई वरना ऐसी किसी ही इस तरह की घटनाएं हैं जो प्रकाश में न आकर घटती हैं।

और गरीबी के कारण माताएं अपनी संतानों को थोड़े से रुपए में बेच कर उन से दूर होने को मजबूर हो चुकी हैं।

निश्चित रूप से कानूनी कसौटी पर और किसी भी लिहाज़ से महिला के इस फैसले का बचाव नहीं किया जा सकता, इसलिए सूचना के आधार पर पुलिस ने बच्चा खरीदने वाले व्यक्ति सहित महिला और अन्य आरोपियों के खिलाफ़ ज़रूरी कार्रवाई की है। ऐसे मामलों में कानून की अपनी बाध्यताएं होती हैं और उसकी औपचारिकता को पूरा करना संबंधित महकमे की ज़िम्मेदारी है। मगर साथ ही यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऐसी समस्याओं से निपटने के क्रम में उसकी जड़ों या मूल बजहों की भी पड़ताल की जाए। महिला ने बेशक कानूनी और सामाजिक व्यवस्था के मुताबिक एक ग़लत विकल्प का चुनाव किया, लेकिन उसके हालात पर गैर करना एक संवेदनशील समाज और व्यवस्था की ज़िम्मेदारी है। आखिर क्या वजह है कि अपने बच्चे को बेचने वाली महिला के सामने कोई ऐसा विकल्प नहीं मौजूद था, जिसके सहारे वह अपना और अपने बच्चे का भरण पोषण कर पाती? अपनी ममता का सौदा करना किसी भी मां के लिए कैसी भावनात्मक त्रासदी से गुज़रना हो सकता है, इसका अंदाज़ा भर लगाया जा सकता है।

प्रश्न है कि गरीबी की वजह से उपजी लाचारी में महिला को अपनी संवेदना से जिस स्तर का समझौता करना पड़ा, उसे वैसी स्थिति से बचाने के लिए हमारे समाज और सत्ता तंत्र ने क्या उपाए किए हैं,

**बाकी पेज 11 पर**

## चीन : सालभर का मातृत्व अवकाश

### जनता को ज्यादा बच्चे पैदा करने के प्रोत्साहन के लिए चीन में ऐसे प्रलोभन दिए जा रहे हैं

चीन ने 42 वर्ष पहले एक परिवार एक बच्चे की नीति अपनाकर अपनी बढ़ती आबादी को क़ाबू करने की कोशिश की थी। पर बूढ़ी होती आबादी के चलते उसने इस नीति से पांच साल पहले ही हाथ खींच लिए। अब वह दो बच्चे पैदा करने की इजाज़त दे रहा है। हालांकि इससे भी फायदा नहीं हुआ। इसे देखते हुए चीन ने इस साल एक परिवार में तीन बच्चों की इजाज़त देने का ऐलान किया है और कई लुभावनी स्कीम भी लागू करने पर विचार हो रहा है। तीन बच्चे पैदा करने की अनुमति देने की सरकार की घोषणा के बाद शानाक्षी समेत 14 चीनी प्रांतों में परिवार नियोजन कानूनों में या तो स्थानीय रूप से संशोधन किया गया है या संशोधनों के माध्यम से नए कानून बनाने के बारे में जनमत संग्रह कराया जा रहा है। पहाड़ियों से घिरे शानकसी प्रांत प्रशासन ने विवाहित जोड़ों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के प्रति प्रेरित करने के लिए 168 दिनों के बजाय 1 साल तक वैतनिक मातृत्व अवकाश देने की बात कही है। ऐसा कर वह जर्मनी और नॉर्वे जैसे यूरोप के कुछ सबसे विकसित देशों की नीति के बराबर खड़ा हो जाएगा। इस साथ ही प्रांत में तीसरे बच्चे के पैदा होने पर पितृत्व अवकाश की अवधि दोगुनी कर 30 दिन की तैयारी चल रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ प्रांतों में छुट्टी का एक नया तरीका सामने आया है। वहाँ 'चाइल्ड रेजिंग लीव' या चाइल्ड केयर लीव के तौर पर छुट्टी की तैयारी है। यह छुट्टी उन विवाहित जोड़ों या माता पिता के लिए है जिनके बच्चे तीन साल से कम आयु के हैं। हैनान में माता पिता को 03 वर्ष से कम आयु के बच्चों की परिवर्शन के लिए हर दिए एक अतिरिक्त घंटे की छुट्टी की पेशकश की गई है। चीन के सुदूर पूर्वोत्तर क्षेत्र में औसत से कम जन्मदर के हड्डोंग जियांग प्रांत में परिवार को 4 बच्चे पैदा करने की अनुमति दे रहा है।

अपने प्रिय अखबार साप्ताहिक शांति मिशन को इंटरनेट पर देखने के लिये लॉगआॉन करें:

[www.aljamiyat.in](http://www.aljamiyat.in) — [www.jahazimedia.com](http://www.jahazimedia.com)

Mob. 9811198820 — E-mail: Shantimissionweekly@gmail.com

## खरीदारी चन्दा

वार्षिक Rs.130/-

6 महीने के लिए Rs.70/-

एक प्रति Rs.3/-

जानकारी के लिये सम्पर्क करें  
**साप्ताहिक**

## शांति मिशन

1, बहादुरशाह ज़फर मार्ग,

नई दिल्ली-110002

फोन : 011-23311455